● वर्ष-3
● अंक-81
रायपुर, शनिवार
11 नवंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› कभी लोकतंत्र के खिलाफ ...

कांग्रेस नेता ने कहा- जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता

कांग्रेस को राम-हिंदू शब्द से दिक्कत : प्रमोद

गाजियाबाद। राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। इन सब के बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए हैं उसे सारी दुनिया जानती है... राम से नफरत कौन करता है और राम के प्रति श्रद्धा किसकी है? मुझे नहीं लगता कि इस रहस्य पर कोई परदा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि सच को सच और झूठ को झूठ न कहा जाए। मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं राम से भी नफरत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह देश का सौभाग्य है कि हम राम मंदिर के उद्घाटन के साक्षी बनेंगे।

कांग्रेस नेता और आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस नेतृत्व पर इस बात के लिए हमला बोला है कि वह हमेशा हिंदू विरोधी रुख अपनाते हैं। आचार्य कृष्णम के मुताबिक यह कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश चुनाव में पार्टी की ओर से जारी चुनाव प्रचार में शामिल नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, पार्टी के लिए परेशान होने का कोई कारण नहीं है। हो सकता है कि पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता हो हिंदुओं का समर्थन या फिर उन्हें एक हिंदू गुरु को स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल किये जाने पर खामी दिखाई दे रही होगी।

बेहद भावुक होते हुए उन्होंने आगे कहा, यह कांग्रेस पार्टी का निर्णय है। मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं, जो भगवान राम से नफरत करते हैं। इन नेताओं को हिंदू शब्द से भी नफरत है। वे हिंदू धार्मिक गुरुओं का अपमान करना चाहते हैं। उन्हें यह पसंद नहीं है कि पार्टी में कोई हिंदू धार्मिक गुरु हो। आचार्य कृष्णम ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक जैसी कोई चीज नहीं बची है।

उन्होंने कहा, इंडिया ब्लॉक बनाने का मुख्य लक्ष्य पीएम मोदी को हराना और बीजेपी सरकार को गद्दी से उतारना था। लेकिन दुख की बात यह है कि विपक्ष मोदी से इतनी नफरत करता है कि वे भूल जाते हैं कि वे भारत से नफरत करने लगे हैं। अगर पीएम मोदी नई संसद का उद्घाटन करते हैं तो वे इसका विरोध करते हैं। अगर ट्रेन का नाम वंदे भारत है तो वे इसका विरोध करते हैं। पीएम की आलोचना करने से कोई नहीं रोकता, लेकिन उनसे नफरत

करना ठीक नहीं है। विपक्ष इतना भ्रमित हो गया है कि सब कुछ भूल गया है। वहीं नीतीश कुमार द्वारा बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण के मामले में महिलाओं के प्रति की गई प्रतिकूल टिप्पणी पर पीएम मोदी के हमले पर अलग रूख अपनाते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर हम हर चीज के लिए बीजेपी और मोदी को दोषी ठहराते रहेंगे तो यह गलती होगी।

उन्होंने कहा, विपक्ष अपनी सारी गलतियों का ठीकरा मोदी पर फोड़ना चाहता है। अखिलेश कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे धोखेबाज पार्टी है। क्या वह मोदी जी के कहने पर ऐसा कह रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के बयान का ठीकरा भी मोदी पर फोड़ा जाएगा? भला इंडिया गुट का कोई नेता क्यों नहीं नीतीश से पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों कहा?

आचार्य कृष्णन ने कहा, बीते 10 सालों से हम बस यही करते रहे हैं। हमारे चेहरे पर धूल थी और हम आईना साफ करते रहे। मुझे नहीं लगता है कि इंडिया ब्लॉक नाम की कोई चीज बची है। अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस ने सपा को धोखा दिया है। आप कांग्रेस पर उंगली उठा रही है। अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर उंगली उठाते हैं। कांग्रेस की ऐसी तीखी आलोचना के बाद बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर आचार्य प्रमोद ने कहा कि अगर कोई भारत, सनातन की बात करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह बीजेपी में शामिल होना चाहता है। उन्होंने कहा, सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, सवाल भारत की संस्कृति और सभ्यता का है।

हिंदुओं की वजह से लोकतंत्र कायम : जावेद अख्तर

मुंबई। वरिष्ठ कवि और गीतकार जावेद अख्तर ने गुरुवार को सहिष्णु होने के लिए हिंदू समुदाय की प्रशंसा की और कहा कि भारत में लोकतंत्र हिंदू संस्कृति और परंपरा के कारण मौजूद है। अख्तर ने समाज में असहिष्णुता बढ़ने पर चिंता जताते हुए कहा कि हिंदू उदार और बड़े दिल वाले होते हैं। 78 अख्तर ने कहा कि कुछ लोग हैं जो हमेशा असहिष्णु रहे हैं। हिंदू ऐसे नहीं हैं। उनके पास उदार और बड़े दिल वाले जैसे यह महान गुण है। इसे मत खोएं, अन्यथा आप दूसरों की तरह बन जाएंगे। मुंबई में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) द्वारा आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में ठाकरे मौजूद थे।

अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री के सामने भारत ने खोल दी कनाडा की पोल

नईदिल्ली। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि 2+2 चर्चा में दोनों पक्षों के प्रमुखों भारतीय पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और अमेरिका की ओर से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की। हमने कई

साझेदारियों पर चर्चा की गई। व्यापार और निवेश साझेदारी, प्रौद्योगिकी साझेदारी, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र से संबंधित साझेदारी, विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला प्रतिभूतिकरण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में साझेदारी, हमारी निरंतर भागीदारी, खनिज प्रतिभूतियों का क्षेत्र, आतंकवाद से निपटने में हमारे साझा प्रयास ये सब द्विपक्षीय संबंधों के अवलोकन का हिस्सा बने।

टू प्लस टू मीटिंग में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयन ऑस्टिन की अगुवाई वाले पूरे अमेरिकी दल-बल के सामने भारत ने कनाडा की पोल खोल कर रख दी। बैठक के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का पनाहगाह बना हुआ है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि जहां तक कनाडा का सवाल है, हम अपने सभी दोस्तों और साझेदारों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और इस मामले पर हमारी स्थिति कई मौकों पर पूरी तरह से बताई गई है। मुझे यकीन है कि आप सभी उस हालिया वीडियो से अवगत हैं जिसमें एक व्यक्ति गुरपतवंत सिंह पन्नू बहुत गंभीर सुरक्षा चिंताओं को प्रस्तुत करता है। क्वात्रा ने जिस वीडियो की तरफ इशारा किया वो खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू से जुड़ा है। वो बार-बार वीडियो जारी कर भारत को धमकियां दे रहा है।

दिवाली का त्योहार आ चुका है और इस बार फिर से दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में नया रिकॉर्ड बनने की तैयारी हो गई है। अयोध्या में नरक चतुर्दशी (छोटी दिवाली) के मौके पर 11 नवंबर को अयोध्या में 24 लाख दीयों को एक साथ जलाकर रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी है।

पंजाब सरकार और राज्यपाल को लगाई फटकार

नईदिल्ली। विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच चल रही खींचतान के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जो कुछ कहा है उस पर सभी राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को ध्यान देना चाहिए। देखा जाये तो विधानसभा का सत्र नियम अनुसार ही चले, राज्यपाल विधेयकों को %राजनीतिक कारणों% से लटकाएं नहीं तथा मुख्यमंत्री और राज्यपाल एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान नहीं दें तो राज्यों में इस तरह के विवाद देखने को नहीं मिलेंगे।जहां तक पंजाब का विवाद है तो आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने को लेकर पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच जारी गतिरोध को शुक्रवार को %गंभीर चिंता% का विषय बताते हुए कहा है कि राज्य में जो हो रहा है उससे वह खुश नहीं है। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पंजाब सरकार और राज्यपाल दोनों से कहा, ''हमारा देश स्थापित परंपराओं और

परिपाटियों से चल रहा है और उनका पालन करने की जरूरत है।'' पीठ ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति नहीं देने के लिए पंजाब के राज्यपाल पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा ''आप आग से खेल रहे हैं।'' साथ ही पीठ ने विधानसभा सत्र को असंवैधानिक करार देने की उनकी शक्ति पर सवाल उठाया।पीठ ने पंजाब सरकार से भी सवाल किया कि उसने विधानसभा के बजट सत्र की बैठक को स्थगित क्यों किया, सत्रावसान क्यों नहीं किया गया।

पीठ ने कहा कि वह विधेयकों को मंजूरी देने की राज्यपाल की शक्ति के मुद्दे पर कानून तय करने के लिए एक संक्षिप्त आदेश पारित करेगी। हम आपको यह भी बता दें कि छह नवंबर को शीर्ष अदालत ने कहा था कि राज्य के राज्यपालों को इस तथ्य से अनजान नहीं रहना चाहिए कि वे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं। अदालत ने राजभवन द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई नहीं करने पर अपनी चिंता व्यक्त की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया था।हम आपको यह भी बता दें कि पंजाब सरकार ने पूर्व में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की ओर से मंजूरी देने में देरी का आरोप लगाते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

प्रमुख समाचार

अखनूर सेक्टर पर जवानों के साथ दीवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री

नईदिल्ली।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के द्वारा स्थापित परंपरा के मुताबिक इस बार भी दिवाली जवानों के साथ मनाएंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जवानों

के साथ दीवाली मनाएंगे। दिवाली के दिन प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वह अखनूर सेक्टर जा सकते हैं। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है।भारतीय सेवा के 191 ब्रिगेड के साथ दिवाली के अवसर पर पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। इस दौरान अखनूर सेक्टर में बीएसएफ के जवान भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जवानों का उत्साहवर्धन करेंगे। माना जा रहा है कि हमेशा की तरह प्रधानमंत्री इस मौके पर अपना संबोधन भी दे सकते हैं। पूरे देश में दिवाली की तैयारी चल रही है। पिछले साल दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल में थे जहां उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया था। 2021 में उन्होंने नौसेरा सेक्टर में सैनिकों के साथ दीपावली मनाई थी।2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर गए थे जहां उन्होंने जैसलमेर में जवानों के साथ दीपों का पर्व मनाया था। राजौरी में वह 2019 में थे।

महुआ पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर विपक्ष की आपत्ति

नईदिल्ली। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश करने वाली लोकसभा आचार समिति में विपक्षी सदस्यों ने अपने

असहमति नोट में कहा कि पैनल ने अपनी जांच अनुचित जल्दबाजी और संपूर्णता की कमी के साथ की। कैश-फॉर-क्वेरी आरोपों की जांच को कंगारू कोर्ट द्वारा फिक्स्ड मैच बताते हुए विपक्षी नेताओं ने एथिक्स कमेटी के जनादेश पर सवाल उठाए और कहा कि मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से की गई थी और यह एक खतरनाक स्थिति पैदा करेगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा मोइत्रा के खिलाफ आरोपों की जांच के बाद पैनल की रिपोर्ट को इसके पक्ष में छह सांसदों और विपक्ष के चार सांसदों के मतदान के बाद अपनाया गया।अपने असहमति नोट में बसपा के दानिश अली, कांग्रेस के वी वैथीलिंगम और उत्तम कुमार रेड्डी, सीपीआई (एम) के पीआर नटराजन और जेडी (यू) के गिरिधारी यादव ने कहा कि मोइत्रा को व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से जिरह करने का मौका नहीं दिया गया। उन पर अपना संसद लॉगिन और पासवर्ड साझा करने का आरोप है।

दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी पर बेटे को फायदा पहुंचाने का आरोप

नईदिल्ली।दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार एक बार फिर भ्रष्टाचार के मामले में सुर्खियों में हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुमार पर अपने बेटे की कंपनी को 315 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाने का आरोप है। यह मामला द्वारका एक्सप्रेस-वे में हुए जमीन घोटाले से जुड़ा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित तौर पर शिकायत को जांच के लिए सतर्कता मंत्री के पास भेज दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, द्वारका एक्सप्रेसवे सड़क परियोजना के लिए बामनोली गांव में 19 एकड़ जमीन के लिए 18.54 करोड़ रुपये प्रति एकड़ का भुगतान किया गया है। यह रकम दो लोगों को दी गई। इस जमीन के लिए कुल 353 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। सूत्रों ने कहा कि 2018 में इस जमीन की कीमत केवल 41 करोड़ रुपये थी और दिल्ली के डीएम आईएएस हेमंत कुमार ने इस जमीन के लिए 343 करोड़ रुपये का मुआवजा जारी किया था। गौरतलब है कि मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे का कंपनी में कनेक्शन है जिसे इस मुआवजे से फायदा हुआ है। हालांकि, मुख्य सचिव कुमार ने कहा कि उनका बेटा खुद पर निर्भर है।

12 साल बाद भारत-मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक

नईदिल्ली।विदेश मंत्री एस जयशंकर और मलेशिया के विदेश मंत्री जाम्ब्री अब्द कादिर के बीच भारत-मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक 7 नवंबर को हुई। इसने हाल के वर्षों में कई अड़चनों

के बाद भारत-मलेशिया संबंधों को फिर से पटरी पर ला दिया। पूर्व विदेश मंत्री सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने आसियान के साथ भारत की साझेदारी के 30 साल पूरे होने के अवसर पर जून 2022 में विशेष भारत-आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। चूंकि मलेशिया की आंतरिक राजनीति प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के तहत स्थिर हो गई है, इसलिए साझेदारी का एक बड़ा इरादा स्पष्ट है।पिछली बैठक 2011 में होने के बाद से 12 वर्षों के अंतराल के बाद, संयुक्त आयोग की छठी बार बैठक हुई है। महामारी के कारण कुछ देरी को शायद माफ कर दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं ध्यान भटक गया है और विचारों में भिन्नता है। इसलिए जेसीएम जुड़ाव की पुनर्स्थापना और पुराने संबंधों का पुनरुद्धार है। मलेशिया आसियान के मूल सदस्यों में से एक है।

2 पत्रकारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश

नईदिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि फाइनेंशियल टाइम्स के दो पत्रकारों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए, जिन्हें गुजरात पुलिस ने अडानी समूह की कंपनियों के संबंध में अखबार में

प्रकाशित एक लेख के संबंध में प्रारंभिक जांच के लिए बुलाया था। दो संवाददाताओं बेंजामिन निकोलस ब्रूक पार्किन और क्लो नीना कोर्निश की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति बी आर गवई और पी के मिश्रा की पीठ ने इसे 1 दिसंबर को सुनवाई के लिए तय किया और निर्देश दिया कि तब तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय जाने के बजाय सीधे उससे संपर्क करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। न्यायमूर्ति गवई नेकहा कि यह चलन अब बहुत कठिन होता जा रहा है, हर कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहा है। पत्रकारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि वे लेख के लेखक नहीं थे बल्कि नई दिल्ली और मुंबई में तैनात संवाददाता थे। उन्होंने यह भी बताया कि 3 नवंबर को, इसने दो अन्य लोगों को बलपूर्वक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की थी, जिन्होंने अदानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर एक और लेख लिखा था।

नीतीश कुमार को शर्मिंदा होना चाहिए, उस पर गर्व कर रहे

संतोष पाठक

बिहार की जेडीयू-आरजेडी गठबंधन सरकार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना से जुड़े आंकड़ों को पेश कर दिया। सरकार ने इन आंकड़ों में राज्य में आबादी की शैक्षणिक स्थिति के बारे में जानकारी दी है। यह भी बताया कि राज्य में किस जाति में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। किस जाति के कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं।

विपक्षी दलों के हंगामा के बीच जिस अंदाज में बिहार सरकार ने इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार शायद देश का इकलौता ऐसा अनोखा राज्य है जिस राज्य में कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को बिहार की दुर्दशा के पाप से अलग नहीं रख सकता है। बिहार की दयनीय हालत का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जिस रिपोर्ट पर वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वहां के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एवं उनके पिता लालू यादव और कुछ हद तक विपक्षी भाजपा को भी शर्मिंदा होना चाहिए। उस रिपोर्ट को नीतीश सरकार ने गर्व के साथ सदन के अंदर पेश कर दिया।

बिहार में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर 1990 में भाजपा के समर्थन से लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1990 में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे। राबड़ी देवी के भाइयों के बढ़ते प्रभाव और नीतीश की मौजूदगी में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव द्वारा

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के साथ किए गए व्यवहार के बाद नीतीश कुमार ने लालू यादव से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। भाजपा के साथ मिलकर लड़ते रहे। और फिर फाइनली 15 साल बाद वर्ष 2005 में नीतीश कुमार, लालू परिवार (राबड़ी देवी) को बिहार की सत्ता से हटा कर बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद नीतीश कुमार लगातार 8 साल तक भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री रहे। भाजपा ने सिर्फ समर्थन ही नहीं दिया बल्कि सरकार में शामिल भी रही। नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय फलक पर आने के बाद नीतीश कुमार कभी भाजपा के साथ तो कभी लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाते रहे। नीतीश कुमार के उपमुख्यमंत्री और मंत्री तो बदलते रहे लेकिन मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार के पास ही रहा। पहले लालू यादव फिर उनकी पत्नी और फिर नीतीश कुमार, ये तीनों मिलकर 1990 के बाद से बिहार पर राज कर रहे हैं, यानी पिछले 33 वर्षों से बिहार के भाग्य विधाता बने हुए हैं और उसके बाद भी बिहार की हालत कितनी दयनीय हो गए हैं, यह इन्ही की सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए आंकड़े बताते हैं।

जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। बिहार सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़े के मुताबिक राज्य में 32.1 फीसदी लोग ऐसे हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं। बिहार की 22.67 आबादी ने सिर्फ पहली से पांचवी तक की शिक्षा हासिल की है। कक्षा 11 से 12 तक पढ़ने वाले लोगों का आंकड़ा सिर्फ 9.19 फीसदी है और बिहार में ग्रेजुएट तक कि पढ़ाई करने वाले लोग सिर्फ 7 फीसदी ही है। सामान्य वर्ग की बात तो छोड़ ही दीजिए लेकिन जिस धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के नाम पर लालू-नीतीश पिछले 33 वर्षों से बिहार पर राज कर रहे हैं उस बिहार में मुसलमानों की बात करें तो 25.84 फीसदी शेख गरीब है। पठान में 22.2 फीसदी और सैयद में 17.61 फीसदी परिवार अभी भी गरीब है। सामाजिक न्याय के नाम पर मसीहा बनने वाले लालू/नीतीश के 33 वर्षों के राज के बावजूद 29.87 फीसदी तेली, 34.56 फीसदी मल्लाह, 32.99 फीसदी कानू, 34.75 फीसदी धानुक, 35.88 फीसदी नोनिया,38.37 फीसदी नाई परिवार गरीब है।किसी भी राज्य पर 33 वर्षों तक राज करने वाले राजनीतिक दलों के लिए यह आंकड़ा अपने आप में काफी शर्मनाक है कि आज भी बिहार में सामान्य वर्ग में गरीब परिवारों की संख्या 25.09 फीसदी है। आरक्षण का लाभ हासिल करने के बावजूद, पिछड़ा वर्ग के तहत आने वाले लोगों में 33.16 फीसदी परिवार गरीब हैं तो वहीं अत्यंत पिछड़ा से ताल्लुक रखने वाले 33.58 फीसदी परिवार गरीब हैं। अनुसूचित जाति में 42.93 फीसदी गरीब परिवार हैं तो वहीं अनुसूचित जनजाति में 42.70 फीसदी परिवार गरीब है।

बिहार की इस हालत के लिए निश्चित तौर पर बिहार में राज करने वाले नेता तो जिम्मेदार हैं ही लेकिन इसके साथ-साथ बिहार के मतदाता भी कम जिम्मेदार नहीं है क्योंकि इस बुरी हालत के बावजूद बिहार के हुक्मरान बड़े गर्व के साथ इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश कर रहे हैं और आरक्षण का लॉलीपॉप देकर एक बार फिर से सामाजिक न्याय के नाम पर दलित, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग से आने वाली जातियों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं और जनता इन्हें मसीहा बना भी देगी।

छत्तीसगढ़ में यहां हाथी लोगों को वोट तक डालने नहीं देते, सरगुजा के कई हिस्सों में आतंक

सरगुजा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान में बस्तर संभाग की 12 सीटों के साथ दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदान हुआ। वहीं अब दूसरे चरण में बची 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोटिंग है। दूसरे चरण के चुनाव में 958 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। सेकंड फेज के चुनाव में कई विधानसभा सीट ऐसी हैं, जो हाथी के आतंक से प्रभावित हैं। यही वजह है कि इस चुनाव में हाथी का भी मुद्दा छाया है।

गरियाबंद, महासमुंद, कोरबा, रायगढ़, धरमजयगढ़, सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर जैसे जिले हाथी प्रभावित हैं। इन इलाकों में हाथी अक्सर किसानों की फसल और घरों को निशाना बनाते रहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन इलाकों में हाथी सक्रिय हैं, क्या वहां के मतदाता वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे।

सरगुजा जिले में उदयपुर, मैनपाट और लुंड्रा विकासखण्ड में हाथी लगातार सक्रिय रहते हैं। हाथियों का सबसे अधिक आतंक सूरजपुर जिले में देखा जाता है। यहां के प्रतापपुर विकासखण्ड में हाथी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। प्रतापपुर के किसान सबसे ज्यादा गन्ना उगाते हैं। इसलिए हाथियों का रुख इस ओर सबसे ज्यादा रहता है। बलरामपुर जिले का रामचंद्रपुर विकासखण्ड भी हाथी प्रभावित है। वहीं सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विकासखण्ड के कुछ गांव में भी हाथियों का आतंक भी बना रहता है।

इसके बावजूद इन इलाकों में स्वीप की टीम निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लगातार मतदाता जागरूकता फैला रही है, लेकिन इस टीम के पास भी हाथियों का हल नहीं है।

ग्रामीण रवींद्र गुप्ता ने कहा प्रतापपुर के गणेशपुर, धरमपुर, मदनपुर, गोटगवा, बंशीपुर क्षेत्र में अक्सर हाथी आते हैं, अन्य क्षेत्रों में तो हाथी रात में आते हैं।लेकिन इन गांवों में इतने हाथी हैं कि दिन में भी मुख्य मार्ग और आबादी वाले क्षेत्र में दिखाई दे जाएंगे।

सरगुजा और रायगढ़ की सीमा पर मैनपाट की तराई में मौजूदा समय में हाथी मौजूद हैं। वर्तमान में यहां 13 हाथियों का दल है। जिले के सरभंजा, केसरा, कंडराजा, डांड़केसरा, बावपहाड़, पुरंगा क्षेत्र के जंगलों में हैं। ग्रामीणों में भय का माहौल है। यदि मतदान के पहले हाथी गांव में पहुंचते हैं तो यहां मतदान प्रभावित हो सकता है।

केदार यादव ने कहा हमारे गांव में 9 हाथी हैं, हाथी कभी भी आ जाता है, उसके आने का कोई टाइम नहीं है। आने से फसल का नुकसान होगा, घर का नुकसान होगा। आदमी को पाएंगे तो पटक देंगे तो वो मर जाएगा। अभी यहां 4 हमले हो चुके हैं। मतदान के दिन हाथी आएगा तो मतदान करने नहीं जाएंगे। यहां गाय भैंस देखेंगे कि मतदान करने जाएंगे।

जिला प्रशासन की मानें तो हाथी प्रभावित क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी जो उदयपुर के पास मामला आया था, वहां वन विभाग की टीम ने जाकर हाथियों को खदेड़ा था। वहां कोई हाथी अभी नहीं है। कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा कोरबा और रायगढ़ से हाथियों का दल आता है, लेकिन पूरी टीम मुस्तैद है। डर तो है लेकिन मतदान प्रभावित नहीं होगा। लोगों में कॉन्फिडेन्स बिल्डिंग का काम किया जा रहा है।

सरगुजा रेंज में करीब 115 से 125 हाथी हैं। हाथी अपनी मूवमेंट चेंज करते रहते हैं। एलिफेंट रिजर्व के एरिया में वर्तमान में करीब 70 हाथियों का डेरा है। एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर के निर्माण के बाद अब क्षेत्र में हाथियों के लिये अनुकूल माहौल बन रहाम है। जिसमें उनके भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है।

कोंटा में नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार का असर 36 मतदान केंद्रों तक सिमटा

सुकमा। विधानसभा चुनाव के लिए कोंटा विधानसभा के कुल 233 मतदान केंद्रों में से अतिसंवेदनशील इलाकों के 36 मतदान केंद्र को सुरक्षा कारणों से नजदीकी थाना व कैंप के आस-पास स्थांतरित किए गए थे। जिसमें नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार का असर दिखा।

बस्तर संभाग के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में नक्सलियों के आधार क्षेत्र का दायरा 36 मतदान केंद्रों तक सिमट कर रह गया है। स्थांतरित किए गए 36 मतदान केंद्रों में इस बार औसत 21.57 प्रतिशत मतदान हुआ, इसमें से 7 केंद्र ऐसे थे जिनमें मतदान 1 प्रतिशत से भी कम मतदान हुआ। इनमें उरसांगल में 2 , सुरर्पनगुड़ा में 3, चिमलीपेंटा में 4, बैरपल्ली में 5, मोड़ी में 5, कामाराम में 3 एवं एलमपल्ली में 3 वोट पड़े। 5 फीसदी से कम वोटिंग वाले मतदान केंद्र में, पूवर्ती में 10, मोरपल्ली में 47, गोगुंडा में 23, नागराम में 15, पामलूर-2 में 24, करीगुंडम में 39, पेंटापाड़ में 35 व गच्चनपल्ली मतदान केंद्र में 52 वोट डाले गए। 5 मतदान केंद्र में मतदान का प्रतिशत 5 से ज्यादा और 10 प्रतिशत के भीतर था। इनमें गोंडेराम मतदान केंद्र में 56, बगड़ेगुड़ा में 63, सिंगाराम में 66, दुरमा में 24 और मेहता मतदान केंद्र में 28 मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया।

नक्सलियों के बड़े लीडर और नंबर कंपनी 1 के कमाडंर माने जाने वाले नक्सली हिड़मा के गांव पूवर्ती में भी मतदान हुआ है। नक्सलियों की ओर से चुनाव बहिष्कार का असर नक्सली कमांडर के गांव में तो दिखा, फिर भी यहां गिनती के लोगों ने ही मतदान किया। पूवर्ती गांव में कुल 649 मतदाता हैं, इनमें 353 पुरूष और 296 महिला मतदाता है। चूंकि नक्सलियों के नेता इसी गांव के रहने वाला है, ऐसे में यहां चुनाव बहिष्कार का खासा असर देखने को मिला। फिर भी गांव के 5 पुरूषों और 5 महिलाओं ने मतदान किया, यहां मतदान का प्रतिशत 1.57 रहा। कोंटा विधानसभा के कुल 233 मतदान केंद्र में इस बार मतदान का प्रतिशत वर्ष 2018 की तुलना में 8 प्रतिशत ज्यादा मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग से मिले आकड़ों के मुताबिक इस बार 63.14 प्रतिशत मतदान हुआ, वर्ष 2018 में मतदान का प्रतिशत 55.30 था।

बिलासपुर के बोदरी पंचायत के लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार

■ **विकास नहीं तो वोट नहीं का लगाया नारा**

बिलासपुर। रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला बिलासपुर है। बिलासपुर को लोग न्यायधानी के नाम भी जानते हैं। शहर से महज तीन किलोमीटर की दूरी पर बोदरी नगर पंचायत है, जो आज भी विकास की राह देख रहा है। बोदरी नगर पंचायत के वार्ड 10 के लोगों की शिकायत है कि स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने कभी भी विकास का काम नहीं कराया। जिससे उनकी पंचायत विकास की दौड़ में पीछे छूट गई है। नेताओं की बेरुखी से नाराज लोगों ने इस बार मतदान बहिष्कार का फैसला किया है। उन्होंने अपने पंचायत क्षेत्र में किसी पार्टी का झंडा ही लगने नहीं देंने का ऐलान किया है। अब स्थानीय पार्टियों के नेता इस पंचायत क्षेत्र में प्रचार करने से भी डर रहे हैं।

बोदरी नगर पंचायत के वार्ड 10 निवासियों की शिकायत है कि बीजेपी के 15 सालों के शासन काल और

कांग्रेस के पांच सालों के शासन काल में यहां विकास का कोई काम नहीं हुआ। लोग आज भी उसी हालात में जी रहे हैं जैसा पहले था। बिजली, पानी और सड़क, ये तीनों यहां के लोगों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई हैं।

स्थानीय निवासी ने कहा पूरे पंचायत क्षेत्र में एक भी विकास के काम आपको नजर आ जाए तो कहिएगा। नेता बस वोट मांगने के लिए आते हैं। वोट मिल जाने के बाद यहां झांकने तक नहीं आते। जब नेताओं को हमसे मतलब नहीं है तो फिर हम वोट ही क्यों दें।

चुनावी मौसम में जहां प्रचार पूरे चरम पर है ऐसे में आपको बोदरी गांव में एक ही चुनावी झंडा, एक भी प्रचार का बैनर नहीं नजर आएगा। नाराज पंचायत के लोगों का गुस्सा देख राजनीतिक दलों के नेता और उनकी प्रचार गाड़ियां भी यहां नहीं आती हैं। गांव के युवा इस बात पर नजर रखते हैं कि कहीं किसी के छत पर कोई राजनीतिक झंडा तो नहीं लगा रहा, दीवारों पर कोई चुनावी नारे तो नहीं लिख रहा।

बोदरी नगर पंचायत में जिस तरह से लोगों का गुस्सा राजनीतिक दलों के खिलाफ नजर आ रहा है। वह सियासी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है। जनता अब सिर्फ विकास के लिए वोट देना चाहती है और अपने इलाके में विकास के काम देखना चाहती है। झूठे आश्वासन देने वाले नेता और पार्टियों को अब जनता पसंद नहीं करती। ऐसे में ईटीवी भारत की टीम आपसे अपील करती है कि आप अपना वोट बदलाव लाने के लिए जरूर दीजिए।

गुलाब कमरो के बयान पर रेणुका सिंह का पलटवार, बताया नारियल फोड़ने वाला नेता

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। भरतपुर सोनहत में कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरो ने रेणुका सिंह पर एक बार फिर निशाना साधा है।गुलाब कमरो ने रेणुका सिंह को विकास नहीं करने वाला नेता बताया है। गुलाब कमरो ने कहा कि रेणुका अपने संसदीय क्षेत्र में विकास नहीं करा पाई हैं। मैं क्या कहूं मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन ऐसा ऐसा बयान देकर सुर्खियां बटोरने से नहीं मिलेगा।

गुलाब कमरो के मुताबिक 15 साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी। बिजली मध्य प्रदेश से आता था। भूपेश सरकार बनने से बिजली हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से मिल रहा है। रेणुका सिंह को यदि इस्तीफा देने का अगर शौक है तो प्रेम नगर में आप जाकर देख लीजिए जहां की सांसद हैं। वहां इनके बीजेपी पदाधिकारी पोस्टर लगा रहे हैं। आप इनके आदर्श गांव चले जाइए आदर्श ग्राम में अगर 1 रूपये का काम होगा तो बता दें।

कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरो ने कहा अगर इस्तीफा देने का इतना ही शौक है आपको तो 2014 में आपकी सरकार ने कहा था कि हमारी दिल्ली में सरकार बनेगी तो हम सबके खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। किसी के खाते में नहीं आया। अगर दम है अगर हिम्मत है रेणुका सिंह जी आप देकर बताएं तो मैं जान जाऊंगा ।इसलिए आप छोटे-छोटे बातें ना करें।

वहीं गुलाब कमरो के आरोपों पर रेणुका सिंह ने

पलटवार किया है। रेणुका सिंह ने कहा कि गुलाब कमरो केवल नारियल फोड़ते हैं काम नहीं करते। पांच लाख के पुल के काम को लेकर उनके क्षेत्र में उनके कार्यकाल में उनके आदमियों के कारण चूल गांव में सचिव को जान देनी पड़ी। इससे बड़ा गुंडागर्दी का प्रमाण और क्या दे सकते है। पांच लाख के काम की वजह से किसी की जान चली गई।

भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह ने कहा मेरे अपने क्षेत्र में इतनी बड़ी रेलवे योजना 10 हजार करोड़ कोई छोटा नहीं होता है। अंग्रेजों के समय के काम को मैंने पूरा किया है। हमारी जो ट्रेन चल रही है अंबिकापुर से नई दिल्ली गुलाब कमरो को दिखाई नहीं देती क्या। गुलाब को पता होना चाहिए।

रेणुका सिंह के मुताबिक दरिमा में हमारा एयरपोर्ट बन कर तैयार है । ये पता होना चाहिए कि अम्बिकापुर से बरवाडीह सेंसन हो गया है अभी अचार संहिता के कारण बोल नहीं पा रहे जैसे आचार संहिता हटेगी हमारा काम शुरू हो जाएगा । जो सपने दिखती हु उसे पूरा भी करती हूं।

भरतपुर सोनहत में चुनाव का प्रशिक्षण लेने पहुंचे कर्मचारी हुए नाराज

मनेंद्रगढ़/चिरमिरी/भरतपुर। दूसरे चरण के मतदान के लिए सरकारी कर्मचारियो की भरतपुर सोनहत में ट्रेनिंग का आयोजन अधिकारियों ने किया था। इस ट्रेनिंग में कई कर्मचारी ऐसे थे जो 100 से 150 किलोमीटर दूर से ट्रेनिंग के लिए पहुंचे थे। प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने के बाद इन कर्मचारियों से अधिकारियों ने उनका पहचान पत्र मांगा। कर्मचारियों ने कहा कि वो अपना पहचान पत्र लेकर नहीं आएं हैं। जिसपर अधिकारी नाराज हुए और उनको वापस जाकर अपना वोटर आईडी लाने को कहा। प्रशिक्षण लेने आए कर्मचारी अब इस बात से नाराज हैं कि जो जानकारी उनको यहां दी गई उसे पहले दे दी गई होती तो इतनी दिक्कत नहीं होती। चुनाव आयोग ने पहले चरण के सफल मतदान के बाद दूसरे चरण के मतदान के लिए अपनी तैयारियां शुरु कर दी हैं। दूसरे चरण के लिए चुनाव आयोग ने मतदान दल में शामिल होने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए भरतपुर सोनहत विधानसभा में बुलाया। ट्रेनिंग के लिए पहुंचे कर्मचारी अपने साथ फार्म और पहचान पत्र लाना भूल गए। जिसके बाद अधिकारियों ने कहा कि वो अपना फार्म और पहचान पत्र लेकर आएं। कर्मचारी इस बात से नाराज हैं कि अगर उनको पहले ही आयोग की ओर से ये जानकारी दे दी गई होती कि उनको अपने साथ पहचान पत्र और बताया गया संबंधित फार्म भी लेकर आना है तो वो जरूर लेकर आते। अब फार्म और पहचान पत्र लेने के लिए वापस अगर वो अपने घर लौटते हैं तो काफी वक्त तो उनका आने जाने में गुजर जाएगा। प्रशिक्षण के लिए आए कर्मचारियों को अगर समय पर पूरी जानकारी दे दी गई होती तो इन कर्मचारियों की आधी दिक्कत खत्म हो गई होती।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

निर्वाचन ड्यूटी पर लापरवाही डेढ़ हजार कर्मियों को नोटिस

कोरबा। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ की सरकारी मशीनरी को विधानसभा चुनाव संपन्न करने के लिए आवश्यक जिम्मेदारियां दी हैं । बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगाई गई है । देखने को मिल रहा है कि प्रशिक्षण से लेकर अन्य संबंधित कामकाज में कर्मचारी लापरवाही दिखा रहे हैं, जिला प्रशासन कोरबा ने ऐसे मामलों को लेकर डेढ़ हजार कर्मचारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। साल 2018 में चुनी गई सरकार का पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के साथ विधानसभा का चुनाव कराया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की गई है । इसके तहत अलग-अलग स्तर पर प्रशिक्षण से लेकर दूसरी गतिविधियों पर काम किया जा रहा है। प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी और कर्मियों की ड्यूटी इन कार्यों में लगाई गई है और उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ काम करने के लिए कहा गया है। फिर भी अनेक मौके पर अलग-अलग कारण बता कर कर्मचारी काम करने से पीछा छुड़ा रहे हैं।

वन विभाग ने चित्रकोट वन परिक्षेत्र से एक तेंदुआ पकड़ा

जगदलपुर। बस्तर जिले के चित्रकोट वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने करीब 01 वर्ष के तेंदुआ शावक को पकड़ा है। मादा तेंदुआ के साथ उसका शावक पिछले 2 दिनों से इलाके के एक किसान के घर में मुर्गी का शिकार कर रहा था। वन विभाग ने मादा तेंदुआ को पकडने के लिए जाल बिछाया था, जिसमें मादा तेंदुआ का शावक फंस गया। वन विभाग ने तेंदुआ शावक को घने जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चित्रकोट वन परिक्षेत्र के साकरगांव के सरपंच सकरु की बाड़ी में पिछले कुछ दिनों से तेंदुआ मुर्गियों का शिकार कर रहा था। जिसकी जानकारी वन विभाग को मिली थी। फिर वन विभाग ने सकरू की बाड़ी में एक दिन पहले देसी फंदा लगाया। जब गुरुवार की रात मादा तेंदुआ और शावक फिर से मुर्गियों का शिकार करने पहुंचे तो फंदे में फंस गए। मादा तेंदुआ किसी तरह से फंदे से निकलकर जंगल की तरफ चली गई, जबकि शावक वहीं फंसा रहा। सुबह वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे।

बिना बुक किये लगेज ले जा रहे 24 पैकेट जब्त

बिलासपुर। आजाद हिन्द सुपरफास्ट एक्सप्रेस के दिव्यांग कोच में बिना लगेज बुक कराए 24 पैकेट सामान रेलवे वाणिज्यिक टीम ने सघन जांच के दौरान जब्त किये। सामान के बारे में पूछताछ करने पर जब कोई सामने नहीं आया तो इसे रेलवे के मालखाने में जमा किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के मार्गदर्शन में बिना बुक के पार्सल सामानों की परिवहन की रोकथाम हेतु वाणिज्य विभाग द्वारा गाडियों, रेलवे स्टेशनों, प्लेटफार्म तथा पार्सल कार्यालयों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान 7 नवम्बर को हावड़ा-पुणे एक्सप्रेस के दिव्यांग कोच के नीचे 60 पैकेट वजन 1512 किलो तथा 8 नवंबर को पुणे-हावड़ा आजाद हिन्द एक्सप्रेस के दिव्यांग कोच के शौचालय से कुल 24 पैकेट वजन 544 किलो बिना बुक किए लगेज बरामद किया गया। इस कोच के यात्रियों से उपरोक्त लगेज के संबंध में पूछताछ की गई, किसी ने इसे अपना होना नहीं बताया। रेलवे सुरक्षा बल के समक्ष वजन करने के पश्चात पार्सल कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है।

ट्रेन में असुविधा से बचने, कम सामान के साथ करें यात्रा

बिलासपुर। ट्रेन में अधिक सामान के साथ यात्रा करना स्वयं व सह यात्रियों के लिए बोझिल और असुविधाजनक हो सकता है। साथ ही इससे सुरक्षा संबंधी खतरे भी पैदा हो सकते हैं, जैसा कि ट्रिपिंग और गिरना आदि। अधिक सामान गलियारों और दरवाजों को भी अवरुद्ध कर सकता है, जिससे यात्रियों के लिए चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है। इसी के मद्देनजर रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेनों में यात्रा के दौरान टिकटों की श्रेणी के अनुसार डिब्बे के अंदर सामान ले जाने की अधिकतम सीमा तय की गई है। एसी-। श्रेणी में 70 किलो, एसी -।। श्रेणी में 50 किलो, एसी-।।। श्रेणी में 40 किलो, स्लीपर श्रेणी में 40 किलो तथा सामान्य श्रेणी में 35 किलो सामान निःशुल्क ले जाने की अनुमति है। अनुमत सीमा से अधिक सामान के साथ यात्रा करते पाये जाने पर रेलवे नियमानुसार बिना बुक किए गए लगेज के रूप में उस पर जुर्माने की कार्यवाही की जाती है। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने हेतु गाडियों में पार्सल सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

मध्य प्रदेश के व्यापारी से 10 किलो के चांदी के जेवर जब्त

बिलासपुर। मध्य प्रदेश के व्यापारी से करीबन 10 किलो के चांदी के जेवर और नगद रकम पुलिस ने जब्त की है। जांच के दौरान एससटी और पुलिस की टीम ने उनके पास से 9 किलो 461 ग्राम चांदी के जेवर और करीब 1 लाख 4000 नगद सहित बाइक सवार दो लोगों के पास से करीब 6,50,000 जब्त किया है। दरअसल रतनपुर थाना प्रभारी देवेश सिंह ने बताया कि नेशनल हाईवे 130 मदनपुर के पास चैकिंग चलाया जा रहा था। इसी दौरान अन्य राज्यों से आने वाले गाड़ियों की सघन जांच की जा रही थी। इसी बीच एक कार को रोक कर जांच की गई। तभी गाड़ी से अलग-अलग थैली में चांदी की पायल, सिक्के, चांदी के बिस्किट करीब 9 किलो 461 ग्राम चांदी के जेवर और 10,4000 नगद रकम मिले। मध्य प्रदेश सागर मोती नगर के रहने वाले गाडी ड्राइवर ओंकार साहू पिता रमेश लाल साहू जेवर व नगद रकम के संबंध में दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की है।

सरगुजा में होम वोटिंग से असक्षम मतदाताओं को मिली सुविधा

■ **दुर्गम रास्तों और पहाड़ी चढ़कर वोट कराने पहुंचा मतदान दल**

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में पहली बार होम वोटिंग की शुरुआत की गई। जिसमें दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को वोट डलवाने के लिए मतदान दल के सदस्य घर तक पहुंचे हैं। मतदान दल कई किमी दूर दुर्गम रास्तों से होकर लोगों के घर तक पहुंची और घर को मतदान केंद्र बनाकर मतदान कराया गया। निर्वाचन आयोग की इस पहल से मतदाताओं में भरपूर उत्साह दिखाई दिया। मतदाताओं तथा उनके परिवारजनों ने इस हेतु आयोग की तारीफ की और इस सुविधा के लिए धन्यवाद दिया।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शारीरिक रूप से असक्षम मतदाताओं को यह सुविधा दी गई है। जिले में गुरुवार को मतदान कराने का काम शुरू हो गया है। सुबह मत पेटियों एवं बैलेट पेपर लेकर जिला कलेक्टरेट से कुल 20 मतदान दल रवाना हुए।

जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के घर तक पहुंचकर वोट डलवाए गए। इसके साथ ही भटगांव विधानसभा क्षेत्र में भी एक दल ने जिले की सीमा में शामिल 2 मतदाताओं को होम वोटिंग कराई है। अंबिकापुर के पंकज गुप्ता जो 8 वर्ष की उम्र से ही बिस्तर पर पड़े हैं, वो हर बार मतदान करते थे। दिक्कतों के बाद भी परिजन उन्हें किसी तरह मतदान केंद्र तक ले जाते थे। लेकिन इस बार पंकज की तबीयत ज्यादा खराब थी। शायद वो मतदान केन्द्र तक नहीं जाते। लेकिन होम वोटिंग की सुविधा से आज उन्होंने अपने घर पर ही मतदान किया।

होम वोटिंग में सबसे अधिक उम्र की मतदाता अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से जोगीबांध रामपुर की 100 वर्षीय धुमरी बाई रही। चलने-फिरने में असमर्थ अंबिकापुर, मोमिनपुरा के 85 वर्षीय बुजुर्ग कुदरत अली खान ने अपने पुत्र मुसर्रत अली के सहयोग से मत डाला। सबसे कम उम्र के वोटर सीतापुर विधानसभा से 26 वर्षीय दिव्यांग मतदाता सिलास खलखो हैं।

होम वोटिंग के तहत आज लुण्ड्रा विधानसभा में 54 में से 52 वोटिंग की गई, इसमें 02 मतदाता का देहांत हो चुका है, इसलिए यहां वोटिंग आज ही पूरी हो गई है। अम्बिकापुर विधानसभा में 72 मतदाताओं में से 69 ने वोटिंग की है। इनमें दो मतदाता अनुपस्थित रहे और एक का देहांत हो चुका है। अनुपस्थित मतदाता के लिए कल मतदान दल फिर वोटिंग कराने जायेगी। सीतापुर विधानसभा में 46 में से 43 मतदाता ने वोट दिया। इनमें 01 चिकित्सकीय देखभाल में हैं और 02 अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित मतदाताओं के लिए कल 10 अक्टूबर को दोबारा मतदान दल फिर वोटिंग कराने जायेंगे।

जिले के तीनों विधानसभा में कुल 172 बुजुर्गों और दिव्यांगों ने घर से वोट डालने के लिये आवेदन किया था। जिस पर आज विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग मतदान दल इन बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर पहुंचे। मतदान दल द्वारा पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डलवाया गया। घर पर मतदान के दौरान गोपनीयता और सुरक्षा का खास ख्याल भी रखा गया। मतदान के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट बनाया गया था। वोट डालने में असमर्थ मतदाताओं के लिए परिवार के किसी सदस्य को सहयोगी के रूप में शपथ पत्र भरकर वोट डलवाने में मदद करवाया गया। दुर्गम रास्तों पर चलकर मतदान दल दूरस्थ गांवों में होम वोटिंग कराने पहुंचे। होम वोटिंग में जिले के लुण्ड्रा विधानसभा के ग्राम बरौली की 81 वर्षीय मतदाता सुकनी को होम वोटिंग कराने मतदान दल 5 किमी पहाड़ी रास्ते पर चढ़कर मतदान कराने पहुंचा। निर्वाचन आयोग की इस पहल से होम वोटिंग के माध्यम से ऐसे मतदाताओं को बेहद सहूलियत हुई है।

कथित पत्रकार पर आरटीआई लगाकर ब्लैकमेल करने का आरोप

कांकेर। कांकेर के शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य बी समुंद ने कॉलेज परिसर में ही जहर खा लिया, जिससे उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। कांकेर में इलाज के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया है। जहां इलाज जारी है। प्राचार्य की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने शहर के एक पत्रकार पर बीस लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया हैं। मामला जिले के कांकेर थाना क्षेत्र का है।

दरअसल पूरी घटना दो नवंबर की है। प्राचार्य के बेटे ने सुबह सुसाइड नोट मीडिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें प्राचार्य ने शहर के पत्रकार पर आरटीआई लगाकर ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके अलावा 20 लाख रुपये नहीं देने पर नौकरी जाने, जेल भेजने जैसी धमकी देने का भी आरोप लगाया है।

प्राचार्य ने सुसाइड नोट पर लिखा कि आरटीआई का जवाब न मांग कर रोजाना उनके निजी नंबर पर फोन कर पैसे की मांग करता था। प्राचार्य की सेवानिवृत्ति में एक साल का ही समय बचा है, जिस पर उक्त पत्रकार ने उन्हें पेंशन जैसे प्रकरण में भी दिक्कत आने की धमकी लगातार दी जा रही थी। जिससे परेशान होकर प्राचार्य ने जहर का सेवन किया था ।

संक्षिप्त समाचार

निर्वाचन लेखा व्यय में अंतर, महंत रामसुन्दर दास को जारी हुआ पत्र

रायपुर। विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान प्रत्याशियों के निर्वाचन लेखा व्यय की जांच लगातार की जा रही है। व्यय प्रेक्षक लगातार प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर नजर रख रहें है। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी महंत रामसुन्दर दास को रिटर्निंग ऑफिसर ने लेखा व्यय मिलान के लिए पत्र जारी किया है। 06 नवम्बर की स्थिति में महंत रामसुन्दर दास प्रस्तुत घोषणा और लेखा व्यय के छाया प्रेक्षण पंजी में परिकलित व्यय में अंतर होने के कारण यह पत्र जारी किया गया है। निर्वाचन अधिकारी द्वारा शीघ्रता से निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का मिलान कराने का निर्देश प्रत्याशी को दिए है।

बिलासपुर महापौर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टी संगठन के खिलाफ अर्नगल वार्तालाप करते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण, जारी कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब प्राप्त नही होने के कारण श्री रामशरण यादव, महापौर नगर पालिक निगम, बिलासपुर को आज दिवस 10 नवम्बर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इंडियन नेशनल कांग्रेस) की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है।

मनीष शिशिर व सुरेश हुए कांग्रेस से 6 सालों के लिए निष्कासित

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल मरकाम को कोण्डागांव से पार्टी बनाया था और यहां पर 7 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी जांच में पाया कि अधिकृत प्रत्याशी के विरूध्द पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण कोण्डागांव के मनीष श्रीवास्तव, श्री शिशिर श्रीवास्तव एवं सुरेश पाटले को शुक्रवार पार्टी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के आदेश पर किया गया। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

भाजपा मछुवारा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक शिवकुमार ने दिया इस्तीफा

बालोद। बालोद जिले में भाजपा को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा जब भाजपा नेता, मछुवारा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक, जिला कार्यकारिणी सदस्य, देवरी के शक्ति केंद्र प्रभारी, खेरथा मंडल के प्राथमिक एवं सक्रिय सदस्य शिवकुमार धरमगुडे ने भाजपा की प्राथमिक सक्रिय सदस्यता एवं पार्टी के विभिन्न पदों से त्याग पत्र दे दिया है। अपना त्यागपत्र उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव को भेजा है। भेजे गए त्याग पत्र में उन्होंने कहा है कि वे विगत 33 वर्षों से भाजपा के विभिन्न पदों का दायित्व निष्ठापूर्वक निर्वहन किया है, लेकिन विगत वर्षों से पार्टी में वे खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं जिसकी वजह से वे पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं।

दिव्यांग आसमा को एक दशक के बाद मिला वोटिंग का अवसर

रायपुर। निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांगजनों को भी होम वोटिंग कराया जा रहा है। उनमें मतदान करने का जब्जा भी दिख रहा है साथ ही वे आयोग की इस पहल के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। दक्षिण विधानसभा में टिकरापारा की रहवासी आसमा अशरफी आज अपनी खुशी बया नहीं कर पा रही थी, जब मतदान दल उनके घर वोट कराने पहुंचा उस समय वह बिस्तर मे थी क्योंकि उन्हे चलने फिरने में तकलीफ है। पहले उनके पहचान पत्र तथा रजिस्टर में हस्ताक्षर इत्यादि प्रक्रिया पूर्ण की गई। उसके बाद उन्होंने मतपत्र पर अपने मनपसंद अभ्यर्थी को गुप्त रुप से चिन्हाकित किया। फिर उसे फोल्ड कर मतपेटी में डाला। इसके बाद उनके चेहरे पर संतुष्टी के भाव उमड़ पड़े।

मोदी सरकार पूरे देश में 3100 में ले धान 500 रुपये में दे सिलेंडर : राजीव शुक्ला

रायपुर। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में एक पत्रकारवार्ता ली। इस दौरान शुक्ला ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला।

मोदी की गारंटी के नाम से जारी किए गए घोषणा पत्र को लेकर शुक्ला ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धान की कीमत 3100 क्यों नहीं कर देते। ऐसा करने पर छत्तीसगढ़ के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि 3800 रुपये मिलेगी। शुक्ला ने कहा कि भाजपा पूरे देश में 500 रुपये में सिलेंडर देने का ऐलान करें इसके बाद कांग्रेस सरकार की सब्सिडी मिलकर मुफ्त सिलेंडर लोगों को मिलेगा।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता को महंगाई से राहत नहीं मिली है, 15 लाख रुपए देने का वादा जुमला बनकर रह गया है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार से विपक्ष कि राज्य सरकारों को कोई मदद नहीं मिल रही है। आगे राजीव शुक्ला ने कहा कि कोई एक भी गारंटी बता दे जो मोदी ने पूरी की हो, गंगा साफ नहीं हुई, भाजपा फिर छत्तीसगढ़ में

किसके भरोसे वादे कर रही है। भाजपा सिर्फ जनता को ठगने का काम करती है। कांग्रेस सरकार में हुए कार्यों का श्रेय लेने में भाजपा लगी हुई है।

प्रेसवार्ता में राजीव शुक्ला ने भाजपा पर सवाल भी दागे। शुक्ला ने पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं ? क्या मोदी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं ? क्या मोदी के चेहरे पर छत्तीसगढ़ में भाजपा चुनाव लड़ रही है ? क्या भाजपा के पास छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं है ? पहले चरण के मतदान को लेकर राजीव शुक्ला ने कहा कि इस चरण में हमारी स्थिति मजबूत है, दूसरे चरण में हम मजबूती के साथ जीत रहे हैं। कांग्रेस की सरकार फिर से बनने जा रही है। शुक्ला ने कहा कि भाजपा का झूठ नहीं चलने वाला है। कर्नाटक की तरह छत्तीसगढ़ की जनता भी भाजपा को करारा जवाब देने जा रही है।

चुनाव हारता देख बृजमोहन अग्रवाल नौटंकी कर रहे : कांग्रेस

भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल द्वारा अपने ऊपर हमले के दावों को प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है, यह चुनाव हारते हुये प्रत्याशी की नई नौटंकी है। बृजमोहन अग्रवाल का सारा चुनावी मैनेजमेंट महंत रामसुंदर दास की सरलता और निश्छलता के सामने फेल हो गया है। बृजमोहन अग्रवाल का दक्षिण से चुनाव हारना तय है, दक्षिण की जनता ने अबकी बार बृजमोहन से छुटकारा पाने का मन बना लिया है। दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशी महंत रामसुदंर दास सरल सहज और सहृदयी संत है। वे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े धर्म गुरू है। उनकी मृदुभाषी आचरण से रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मतदाता उन्हें हाथों हाथ ले रहे, क्षेत्र के महिला, पुरूष सभी महंत जी की जीत सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है। दक्षिण क्षेत्र में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनाव प्रचार कार्यक्रम भी था। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उमड़े जनसैलाब महंत श्री रामसुंदर दास को मिल रहे जनसमर्थन से बृजमोहन अग्रवाल बौखला गये है। बौखलाहट में वे सहानुभूति पाने नौटंकी कर रहे है। शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास की लोकप्रियता के सामने बृजमोहन और भाजपा अपना पसंदीदा सांप्रदायिकता का गंदा खेल भी नहीं खेल पा रही है तो क्षेत्र में तनाव पैदा करने की नीयत से वे हमले की झूठी कहानी गढ़ रहे है।

पांच राजयोग के साथ होगी लक्ष्मी पूजा

रायपुर। 12 नवंबर को मनाया जाने वाला दीपावली का त्योहार इस बार कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को दीपावली के दिन पांच राजयोग का निर्माण हो रहा है इस दुर्लभ योग में धन की देवी लक्ष्मी का पूजन से घर में धन धान्य और समृद्धि आने वाली है। दीपावली पर अमावस्या तिथि 12 नवंबर को दोपहर करीब 2 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक दीपावली की शाम के समय जब लक्ष्मी पूजा होगी तब सभी राजयोग का निर्माण हो रहा है। पंडितों से मिली जानकारी के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर दीपावली मनाने का विधान होता है। दीपावली पर लक्ष्मी व गणेश जी की पूजा साथ में होती है। लक्ष्मी पूजा के लिए प्रदोष काल का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस वर्ष प्रदोष काल के दौरान 5 राजयोग का निर्माण भी होगा। इसके अलावा आयुष्मान, सौभाग्य और महालक्ष्मी योग भी बनेगा। इस तरह से दीपावली 8 शुभ योगों में मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्य का मनाना है कि दीपावली पर इस तरह का शुभ योग कई दशकों के बाद बना है। ऐसे में इस शुभ योग में दिवाली सभी के लिए सुख-समृद्धि और मंगलकामना साबित होने वाला है। इस साल दीपावली पर एक साथ 5 राजयोग देखने को मिलेगा। ये 5 राजयोग गजकेसरी, हर्ष, उभयचरी, काहल और दुर्धरा नाम के होंगे। इन राजयोगों का निर्माण शुक्र, बुध, चंद्रमा और गुरु ग्रह स्थितियों के कारण बनेंगे।

भाजपा विधायक के आरोप पर बोले सीएम बघेल

बृजमोहन पर कौन हमला करेगा उनसे सब डरते हैं : भूपेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राजनीतिक सियासत गरमा गई है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। इस दौरान अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। भाजपा इसे कांग्रेस की साजिश बता रही है। वहीं अग्रवाल के इस आरोप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है।

वर्तमान विधायक बृजमोहन अग्रवाल के आरोप पर सीएम भूपेश ने पलटवार करते हुए कहा कि बृजमोहन अग्रवाल पर क्या कोई हमला कर सकता है? बृजमोहन अग्रवाल के साथ गुंडागर्दी कौन करेगा? अग्रवाल से सब डरते हैं, उन पर कौन हमला करेगा। वहीं, सीएम ने 2000 के एक किस्से का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर भी हमला बोला। यह घटना तब हुई जब बृजमोहन अग्रवाल चुनावी प्रचार के लिए बैजनाथपारा क्षेत्र पहुंचे हुए थे। इस दौरान रायपुर दक्षिण से सात बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। खुलेआम बदमाशों ने उनका कॉलर पड़कर उनसे मारपीट का कोशिश की, लेकिन उन्हें उनके पीएसओ और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बचाकर एक मदरसे में छिपाकर रखा। इस दौरान मदरसे में मौजूद लोगों और कार्यकर्तों ने उनके कुशल क्षेम के लिए कामना की। इसके बाद मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। भाजपा कार्यकर्ता सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर धरने पर बैठ गए। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल खुद भी धरने पर बैठे और मांग की है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक धरना खत्म नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में पुलिस और भूपेश सरकार क्या कारवाई करती है। साथ ही बृजमोहन अग्रवाल का आरोप है कि रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के समर्थकों ने उनके ऊपर हमला किया है। यह सब कांग्रेस सरकार के इशारे पर किया गया है।

हैट्रिक को बेताब कक्का, पाटन में भतीजा और जोगी बने राह का कांटा

रायपुर। दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री कका व सांसद भतीजे की आमने-सामने की लड़ाई में कूदे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़-जोगी (जेसीसीजे) के कर्ताधर्ता अमित जोगी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है।

प्रदेश की सबसे हॉट सीट की चर्चा हर जगह है पर स्थानीय जनता असमंजस में है कि कक्का को चुनें या भतीजे को? असमंजस यह कि कक्का जीते तो सरकार बनने पर मुख्यमंत्री बनेंगे पर भतीजे का क्या? वहीं, अमित जोगी के यहां से मैदान में उतरने की चर्चा तो खूब है पर उनकी पार्टी की सरकार बनाने की लड़ाई में असरदार भूमिका न होने से जनता में विशेष दिलचस्पी नहीं।

पाटन सीट से सीएम भूपेश बघेल के सामने भाजपा के टिकट पर दुर्ग के सांसद विजय बघेल हैं। विजय रिश्ते में भूपेश के भतीजे हैं। दो दिन पहले पत्रकारों ने भूपेश से जब यह पूछा कि कक्का-भतीजे में भारी कौन? इस पर उनका जवाब था, रिश्ते में तो हम बाप लगते हैं... यह जवाब इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। दोनों यहां से चौथी बार आमने-

सामने हैं। इससे पहले हुए तीन मुकाबलों में से दो भूपेश और एक विजय जीत चुके हैं। भूपेश पहली बार वर्ष 1993 में इसी सीट से विधायक चुने गए थे। इसके बाद से लगातार यहीं से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इस बार वह यहां से सातवीं बार मैदान में हैं।

घोषणाओं पर अमल नहीं भतीजा दे रहा टक्कर

पान दुकान पर मिले किसान नरेश पटेल मानते हैं कि भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल अपने कक्का को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उनके अनुसार, सीएम की ओर से की गईं तमाम घोषणाओं पर अमल न होने से यह स्थिति बनी है। यह पूछने पर कि अमित जोगी यहां के चुनाव को कितना प्रभावित करेंगे तो उनका कहना था, क्षेत्र में वह न कभी सक्रिय रहे और न ही उनकी पार्टी का कोई एजेंडा है। ऐसे में वह अधिक से अधिक सतनामी समाज के वोट ही अपने पाले में ला सकेंगे।

कांग्रेस के मुरीद, पर जोगी के जिक्र से चिंतित

पाटन कस्बे के मुख्यमार्ग स्थित चाय की दुकान पर चल रही चुनावी चर्चा में शामिल संजीव वर्मा कांग्रेस की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। यह पूछने पर कि भ्रष्टाचार, घोटालों से घिरी सरकार कितनी चलेगी? उनका कहना था, यह सब भाजपा की देन है। हालांकि, अमित जोगी के जिक्र पर वह थोड़े चिंतित होते हैं। कहा, क्षेत्र में सतनामी समाज का अधिकतर वोट कांग्रेस के पाले में रहता है। अमित यदि एकतरफा वोट बटोर ले गए तो किसका खेल बिगड़ेगा, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते।

कांग्रेस हमास के आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही है : मनोज तिवारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए अपनी ही पार्टी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपराधी बड़े बड़े अपराध को अंजाम देते हैं और आसानी से छूट जाते हैं लेकिन बीजेपी राज में ऐसा नहीं हो सकता।

भाजपा सासंद मनोज तिवारी छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे हैं। रायपुर पहुंचने के बाद मनोज तिवारी ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ की जनता को कोई गलती नहीं करना है। पांच साल पहले यहां की जनता ने एक गलती की, जिसका खामियाजा उन्हें 5 साल झेलना पड़ा।

बाहर के भाजपा नेताओं के छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार करने के कांग्रेस के आरोप

पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि भूपेश बघेल दूसरे प्रदेश में प्रचार के लिए क्या नहीं जाते हैं? ये तभी होता है जब वह डरने लगते हैं। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया में आधा भोजपुरिया है तो मनोज तिवारी क्यों नहीं आएंगे।

मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ये बात छुपाना चाहती है कि कांग्रेस हमास के आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही है। आतंकवादी आते हैं बच्चों और बेटियों की हत्या करती है। फिर उनसे बलात्कार करते हैं। जो हमास का समर्थन कर रहे हैं उनकी मानसिकता को जानिए। मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर सनातन धर्म को नष्ट करने का आरोप लगाया।

बीजेपी सांसद ने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में खुलेआम अपराध होता है लेकिन भाजपा शासक राज्य में यदि कोई गलती से भी अपराध कर ले तो उनकी सात पुश्तें रोयगी कि कहां गलती से अपराध हो गया।

मनोज तिवारी ने महादेव एप मामले पर भी भूपेश बघेल को घेरा। तिवारी ने कहा कि सत्ता में रहकर सट्टा खेलने वाली सरकार नहीं सत्ता में रहकर जनता की सेवा करने वाली सरकार चाहिए।

आचार संहिता का उल्लंघन, शासकीय कर्मचारी निलंबित

रायपुर। विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान शासकीय कर्मचारी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मंदिर हसौद तहसील में पदस्थ कार्यालय सहायक श्री दिनेश कुमार गोस्वामी को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है और सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किए है।

जारी आदेश के अनुसार मंदिर हसौद तहसील कार्यालय में पदस्थ कार्यालय सहायक श्री दिनेश कुमार गोस्वामी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए क्षेत्र में घुम-घुमकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने जनता को प्रोत्साहित कर रहे थे। राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित होकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत पर एसडीएम आरंग ने जांच की थी। जांच में शिकायत सही पाये जाने पर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन पर श्री दिनेश गोस्वामी को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री गोस्वामी को जिला निर्वाचन कार्यालय, सामान्य निर्वाचन शाखा में संलग्न किया गया है।

किसान कर्जमाफी से क्या कांग्रेस को फिर मिलेगी सत्ता की चाबी

कोरबा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर है। दोनों ही पार्टी में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने पिछली बार की तरह इस बार फिर से किसान कर्जमाफी का मास्टर स्ट्रोक खेला है। विपक्षी इसे चुनावी वादा कह रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे भूपेश सरकार की बड़ी उपलब्धि की तरह पेश कर रही है। कांग्रेसियों का मानना है कि घोषणा पत्र में कर्जमाफी का वादा सत्ता में वापसी की चाबी है। विपक्षी दलों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के कई वादों को अधूरा बताया और उनके वादों पर भरोसा नहीं करने की बात कह रहे हैं।

2018 में बीजेपी के 15 साल के शासन के बाद कांग्रेस सत्ता में आई। जिसकी मुख्य वजह किसानों की कर्ज माफी के ऐलान को माना गया। 2018 में कृषि ऋण 3546 करोड़ रुपए था। जो साल दर साल 2023 में बढ़कर दोगुना करीब 6610 करोड़ रुपए हो गया है। यदि सरकार बनने के बाद कांग्रेस किसानों का दोबारा कर्ज माफ करती है, तो उसे 6610 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि का वित्तीय भार वहन करना होगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का यह भी दावा है कि सरकार बनने से लेकर अब तक उन्होंने कुल 9270 करोड़

रुपए का कृषि लोन माफ किया है।

छत्तीसगढ़ एक किसान प्रधान राज्य है। यहां कई आदिवासी और किसान हैं, जो खेती किसानी के लिए बैंक से लोन लेते हैं। ऐसे ही एक किसान सीताराम झरिया कहते हैं कि है कि उन्हें 90 फीसदी उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार बनेगी, तो उनका कर्जा माफ हो जाएगा। उन्होंने बताया, मेरे नाम पर 36 हजार रूपये का लोन सैंक्शन हुआ था। हर साल इतना ही लोन मुझे मिलता है। यह पैसा मुझे वापस चुकाना नहीं पड़ा। सरकार ने यह कर्ज माफ किया था, जिससे मुझे काफी मदद मिल गई थी।

किसान हेतराम राठिया ने कहा सरकार ने पिछली बारी कर्ज माफ किया था। इस बार घोषणा फिर की है। देखते हैं इस बार माफ होता है या नहीं। किसानों का कर्ज माफ हुआ, तो सुविधा मिलती है। उम्मीद तो है कि इस बार भी लोन माफ होगा।

बीजेपी नेता अशोक चावलानी ने कर्जमाफी को लेकर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कर्जमाफी का वादा तो किया, लेकिन इन्होंने सभी का लोन माफ नहीं किया। कई किसानों का लोन माफ नहीं हुआ है। इनके बड़े नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आकर घोषणा करते हैं। इन्हें घोषणा करने का अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस के पिछले घोषणा पत्र के कई वादे अधूरे रह गए थे। इस बार भी यह वादा अधूरा रह जाएगा।

कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष संतोष राठौर ने बीजेपी नेता अशोक चावलानी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस जो वादा करती है, उसे पूरा करती है। मजदूर और किसानों ने देखा है, पिछले बार भी हमारे नेताओं ने कर्ज माफी का वादा किया था और उस वादे को उन्होंने पूरा किया। सरकार जैसे ही बनी 2 घंटे के भीतर कर्ज माफी किया गया। इस बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है। लगभग 20 लाख किसानों ने कर्ज लिया है, जिसे माफ किया जाएगा। कोरबा के स्थानीय कांग्रेसी नेताओं को भरोसा है कि कांग्रेस फिर सत्ता में वापसी करेगी। क्योंकि किसान खुश हैं। उन्होंने कहना है कि पहले न तो समर्थन मूल्य मिलता था, न कर्ज माफी होती थी। कांग्रेस सरकार ने यह काम किया है। जिससे सरकार के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है।

छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा लिए गए कर्ज के आंकड़े

प्रदेश में कुल किसान क्रेडिट कार्ड - 21.23 लाख, प्रदेश में कुल धान खरीदी केंद्रों की संख्या - 2617 केंद्रवर्ष 2023 में कुल पंजीकृत किसान - 24.98 लाख, वर्ष 2023 में कुल दिया गया लोन - 6610 करोड़ रुपए।

कर्जमाफी के वादे पर अधिवक्ता नूतन सिंह ठाकुर कहते हैं, किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र जनता को प्रभावित करने के लिए होता है। प्रदेश में दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। जिसमें कमोबेश एक जैसे वादे हैं। कांग्रेस ने कर्जमाफी की घोषणा को दोहराया है। निश्चित तौर पर इसका असर तो पड़ेगा। आदिवासी और गरीब जनता मुफ्त की चीज प्राप्त करने के लिए आगे आती है। लेकिन यह लोकतंत्र के लिए घातक है। इससे कर्ज लेने की संस्कृति बढ़ेगी। लोग बार-बार कर्ज़ लेंगे। इस उम्मीद में की सरकार माफ कर ही देगी। इसके दूरगामी परिणाम घातक होंगे। लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि इसका भार कहीं ना कहीं आम जनता पर ही पड़ता है। जनता के ही पैसों से कर्ज माफी होती है। इसलिए मुफ्त की रेवड़ी बांटने की संस्कृति पर रोक लगाना भी जरूरी है।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के पहले चरण के तहत 20 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब 17 नवंबर को दूसरे चरण के तहत बाकी के 70 सीटों पर वोटिंग होनी है। जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों के बीच घमासान जारी है। सभी विपक्षी दल कांग्रेस के कर्जमाफी की काट निकालने के लिए अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस इस बार भी कर्जमाफी के भरोसे दोबारा सत्ता हासिल करेगी या फिर बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों के वादों पर जनता मुहर लगाएगी।

मिशन 2024 की तैयारी

स्वदेश कुमार

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दो नावों की सवारी कर रही है। एक तरफ वह प्रदेश में विकास के साथ कानून व्यवस्था मजबूत करने में लगी है तो दूसरी ओर हिन्दुत्व को भी धार दे रही है। योगी सरकार के तमाम फैसले इस बात के संकेत हैं कि योगी सरकार द्वारा अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में हिन्दुत्व की बिसात बिछाई जा रही है। अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण को जहां बढ़-चढ़कर ढिंढोरा पीटा जा रहा है तो अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक भी इसी का एक हिस्सा है। लोकसभा चुनाव 2024 के मिशन को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने धार्मिक एजेंडे को सेट करने में तेजी से लग गई है। इसी कारण योगी सरकार अयोध्या में दीपोत्सव के साथ 9 नवंबर को अपनी कैबिनेट मीटिंग आयोजित की। राजनीतिक जानकर बताते हैं कि भाजपा सरकार मिशन 2024 को साधने के लिए धर्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद व विकास पर तेजी से काम कर रही है। 11 नवंबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव से पहले 9 नवंबर को योगी सरकार की पूरी कैबिनेट यहां बैठेगी। यहां की बैठक के लिए ऐसे प्रस्तावों को चुना गया है, जो धर्म व संस्कृति से जुड़े हुए हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में कैबिनेट बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में अयोध्या से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषक प्रसून कहते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा अयोध्या में कैबिनेट बैठक धार्मिक और राष्ट्रवाद के मुद्दे को धार देने के रूप में देखा जा रहा है। सरकार हर बड़े इवेंट को महत्वपूर्ण बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रम करती हैं, जिससे संदेश भी जाए। इससे पहले 29 जनवरी 2019 को कुंभ मेला के दौरान सभी कैबिनेट मंत्रियों ने गंगा में डुबकी लगाई थी। इसके बाद बैठक की थी। 2017 में सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार के शीर्ष एजेंडे में अयोध्या ही रहा है। सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में भी राजधानी के बाहर एक बार कैबिनेट बैठक की थी। कहते हैं कि योगी सरकार 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को पहले ऐसा माहौल बनाना चाहती है जिसके दूरगामी संदेश हों, और इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी मिले। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी, योगी सरकार और आरएसएस के बीच इस बात को लेकर हमेशा मेल-मुलाकात होती रहती है कि किस तरह से हिन्दुत्व की अलख को जलाये रखा जाये। बीजेपी यूपी में लोकसभा में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर चुकी है और कैसे अपनी मंज़िल तक पहुंचा जाये, इसके लिए हिंदुत्व से लेकर धर्मांतरण तक तमाम ज्वलंत मुद्दों पर पार्टी के भीतर बात होती रहती है। लेकिन, सबसे अहम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति और रणनीति जिस पर संघ को भी भरोसा है। सूत्रों के हवाले से ख़बर है कि मुख्यमंत्री योगी के कामकाज से संघ खुश है। सूत्रों के हवाले से ख़बर है कि क़ानून व्यवस्था के मोर्चे पर संघ योगी सरकार से संतुष्ट है। यानी क़ानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह के कई सख्त फ़ैसले सरकार ने लिए हैं, उससे संघ सहमत है। प्रदेश में क़ानून व्यवस्था को लेकर जनता के बीच जो संदेश है, उसे लेकर संघ के पास सकारात्मक फीडबैक है। सूत्रों का दावा है कि संघ ने इतने बड़े सूबे में क़ानून का राज स्थापित करने के लिए गए योगी सरकार के कई फ़ैसलों को सही ठहराया है। संघ ने क़ानून व्यवस्था को लेकर जो पैमाना तय किया था, वो जनहित में सरकार के प्रति स्वीकार्यता है। संघ ने माना कि योगी सरकार में क़ानून व्यवस्था को लेकर जनता के बीच भरोसे का भाव है। इसलिए इसे और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। साथ ही इस दिशा में खुलकर फ़ैसले लेने पर सहमति जताई गई। ख़बर यह भी है कि बंद कमरे के भीतर हिंदुत्ववादी मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी के मुखर और प्रखर अंदाज़ की संघ भी सराहना करता है। 2017 के बाद से लगातार सीएम योगी को देश के कई राज्यों में हिंदुत्व का पोस्टर ब्वॉय बनाकर प्रचारित किया जा रहा है। संघ को मुख्यमंत्री योगी की ये छवि निखरती नज़र आ रही है। इसी क्रम में अयोध्या में भव्य राम मंदिर से जुड़ी तैयारियों और वहां होने वाले आयोजनों को लेकर कुछ विशेष बातें निकट भविष्य में तय हो सकती हैं।

सुधारों की धीमी हुई रफ्तार

हरीश गुप्ता

पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे चाहे जो भी हों, पिछले कुछ वर्षों के दौरान भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई सुधार प्रक्रिया थम गई है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 में अब तक के सबसे बड़े सुधार के रूप में पारित किया गया था, लेकिन नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता उन प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को दी जानी है जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं और जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है। अधिनियम में मुसलमानों का उल्लेख नहीं है। इस ऐतिहासिक अधिनियम से संबंधित नियम बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने आठवीं बार एक्सटेंशन मांगा है।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) भी पिछले चार वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। इस प्रक्रिया में जनगणना 2021 का पहला चरण कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया था। कोविड खत्म हो गया है लेकिन देश में जनगणना होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। जनगणना में देरी से परिसीमन की प्रक्रिया भी पिछड़ जाएगी, लेकिन मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद जनगणना कराने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा सरकार कोई भी बड़ा चुनावी सुधार लाने में असमर्थ रही है। हालांकि वह चुनावों में कालेधन को खत्म करने के लिए चुनावी बांड को एक प्रमुख हथियार के रूप में प्रदर्शित कर रही है।

यह अलग बात है कि मौजूदा विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग द्वारा की गई भारी नगदी और सामान की बरामदगी इन दावों को झुठलाती है। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी राज्यों और राजनीतिक दलों से कह रहे थे कि वे मुफ्त की संस्कृति को बढ़ावा न दें क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। अब भाजपा विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए रेवड़ियों का वादा करने में सबसे आगे है और प्रतिद्वंद्वियों को काफी पीछे छोड़ दिया है।

मोदी सरकार ने औद्योगिक विकास में तेजी लाने और एक नई कार्य संस्कृति लाने के लिए एक नए युग की शुरुआत करते हुए श्रम क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा सुधार किया। श्रम मंत्रालय द्वारा लेबर कोड 2019-20 में बनाए गए थे। लगभग चार साल होने को हैं लेकिन श्रम संहिताएं अधिसूचित नहीं की गईं। इन संहिताओं के अभाव में विदेशी निवेशकों ने औद्योगिक उत्पादन में उदासीनता बरती है। 29 केंद्रीय श्रम कानूनों के जटिल जाल को तर्कसंगत करने के उद्देश्य से चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन को अनिश्चितकाल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। आरएसएस से जुड़े बीएमएस सहित सभी ट्रेड यूनियनों ने इन संहिताओं को श्रमिक विरोधी बताया है।

लंबी लड़ाई के बाद मोदी सरकार डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट पारित कराने में सफल रही लेकिन सबसे विवादास्पद अधिनियम के नियमों को मंजूरी देना उतना ही कठिन कार्य है और शायद यह संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी पारित न हो पाए। इससे अधिनियमित कानून के कार्यान्वयन में और देरी होने की संभावना है। हालांकि नियम तैयार हैं, लेकिन सरकार इसे पारित कराने की जल्दी में नहीं दिख रही है।

यह संहिता वेतन, औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति व सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। चूंकि श्रम मुख्य रूप से राज्य का विषय है इसलिए कुछ राज्यों ने विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई लाने के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने कानून में सुधार करना शुरू कर दिया है। प्रमुख संशोधनों में से एक यह है कि 100 या अधिक कर्मचारियों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को एक भी स्थायी या अस्थायी कर्मचारी को नौकरी से निकालने या व्यावसायिक इकाइयों को बंद करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी।

हालांकि नई औद्योगिक संबंध संहिता इस सीमा को बढ़ाकर 300 कर देती है और राज्यों को 300 से भी अधिक सीमा निर्धारित करने की अनुमति देती है। सुधारों से निश्चित अवधि के अनुबंधों पर लोगों को रोजगार देने पर लगा मौजूदा प्रतिबंध भी हट जाएगा। असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने अपने राज्य में श्रमिकों के लिए अधिकतम दैनिक कार्यदिवस को बढ़ाकर 12 घंटे करने के लिए अधिसूचनाएं जारी कीं।

लेकिन इसके बाद राजस्थान और यूपी ने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया लेकिन कर्नाटक ने एप्पल के लिए फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन जैसी आईफोन से संबंधित इकाइयों को असेंबल करने के लिए कारखानों में 12 घंटे की शिफ्ट और महिलाओं के लिए रात में काम करने की अनुमति देने वाले श्रम कानून लाए। अब यूपी और तमिलनाडु में भी ऐसे ही बदलाव होने की संभावना है। लेकिन केंद्र मूकदर्शक बना हुआ है।

लंबी लड़ाई के बाद मोदी सरकार डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट पारित कराने में सफल रही लेकिन सबसे विवादास्पद अधिनियम के नियमों को मंजूरी देना उतना ही कठिन कार्य है और शायद यह संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी पारित न हो पाए। इससे अधिनियमित कानून के कार्यान्वयन में और देरी होने की संभावना है। हालांकि नियम तैयार हैं, लेकिन सरकार इसे पारित कराने की जल्दी में नहीं दिख रही है। सरकार इन नियमों पर जनता की राय लेने पर विचार कर रही है क्योंकि अधिकांश कंपनियां अधिनियम के कुछ प्रावधानों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं और उदार दृष्टिकोण चाहती हैं।

पता चला है कि कुछ प्रमुख उद्योगपति डीपीडीपी नियमों को अंतिम रूप देने के बाद उन्हें लागू करने के लिए दो साल की अवधि चाहते हैं। डीपीडीपी मोबाइल फोन, ईमेल अकाउंट या इंटरनेट के किसी अन्य रूप का उपयोग करने वाले लगभग हर भारतीय को प्रभावित करता है। नियम अधिसूचित होने के बाद भी एक लंबी प्रक्रिया है क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्थापना की जाएगी। डिजिटल गोपनीयता के लिए भारत के पहले समर्पित कानून के रूप में, डीपीडीपी अधिनियम डिजिटल रूप में व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह और प्रसंस्करण का व्यापक सिद्धांत प्रदान करता है। अधिनियम इस अर्थ में कठोर है कि इसमें डाटा उल्लंघन के प्रत्येक मामले के लिए 250 करोड़ रुपए तक के मौद्रिक दंड और बार-बार उल्लंघन के मामले में संस्थाओं को ब्लॉक करने का प्रावधान है। आधार, बैंक खातों और अन्य विवरणों के डाटा लीक के मामलों में चिंताजनक वृद्धि से सरकार चिंतित है। हैकर्स ने फेसबुक खाताधारकों में भी सेंध लगा उन्हें असुरक्षित बना दिया है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-38)

गतांक से आगे...

हे परमश्रेष्ठ ज्ञानवान् मुने! मैं ही सभी कुछ हूँ। ऐसा जो दृढ़ निश्चय (संकल्प) है, उसे धारण करके बुद्धि पुन: विषाद को प्राप्त नहीं करती। आत्मा के नाम से कहा जाने वाला शून्य ही प्रकृति, माया, ब्रह्मज्ञान, पुरुष, ईशान, शिव, नित्य एवं ब्रह्मज्ञान आदि के नाम से जाना जाता है। परमात्मस्वरूपा अद्वैत शक्ति ही द्वैत एवं अद्वैत से प्रादुर्भूत हुए पदार्थों से संसार के निर्माण की लीला करके विकसित हो रही है। जो सभी तरह के मायाजाल से परे आत्मरूपी पद का आश्रय प्राप्त करके एक पूर्णरूपेण चिन्मयस्थिति में रहकर न कोई उद्योग करते हैं और न ही संतुष्ट होते हैं। इस जागतिक शोक में वे कभी नहीं पड़ते।

हे पुत्र ! जो मनुष्य नित्य प्राप्त कर्मों को करता है, शत्रु एवं मित्र को सम्यक् दृष्टि से देखता है और इच्छा- अनिच्छा से मुक्ति प्राप्त कर चुका है, न विषाद करता है, न किसी भी तरह की वस्तुएँ पाने की आकांक्षा करता है, मृदुभाषी है, प्रश्नों के पूछने पर नम्रतापूर्वक उत्तर देता है तथा समस्त प्राणियों के भावों को जानने में सक्षम है; वही मनुष्य इस विश्व में विषाद को प्राप्त नहीं होता।

प्रथम दृष्टि (आत्मदृष्टि) को लक्ष्य करके विलास की कामना का त्याग करके सांसारिक ताप से रहित होकर तथा अन्तरात्मा में प्रतिष्ठित होकर इस संसार में जीवन्मुक्त की तरह से भ्रमण करो। सभी प्रकार की आशाओं को हृदय से निकाल कर वीतराग तथा वासना रहित होकर बाह्यमन से सभी सांसारिक रीति-रिवाजों का सम्यक् रूप से पालन करते हुए जगत् में तापविहीन होकर निरन्तर प्रवहमान रहो।

बाह्य वृत्ति से बनावटी क्रोध का अभिनय करते हुए एवं हृदय से क्रोधरहित, बाहर से कर्तृता एवं अन्दर से अकर्ता बने रहकर शुद्धभाव से जगत् में सर्वत्र रमण करो। अहं को त्यागकर शान्त चित्त हो, कलङ्क रूपी कालिमा से सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। आकाश के सदृश शुद्ध-परिष्कृत जीवन प्राप्त करके पवित्र सद्बुद्धि को धारण करके लोक में विचरण करो।

उदार एवं उत्तम आचरण से सम्पन्न, सभी श्रेष्ठ आचार-विचारों का अनुगमन करते हुए अन्दर से आसक्ति रहित होते हुए भी बाहर से सतत प्रयत्न करता रहे। अन्त:करण में पूरी तरह से वैराग्य को धारण करते हुए बाहर से आशावादी बनकर श्रेष्ठ व्यवहार करे। यह मेरा अपना (मित्र) है और वह नहीं है, ऐसे निकृष्ट विचार क्षुद्र मनुष्यों के होते हैं। उदार चरित वालों के लिए तो समस्त वसुधा ही अपना परिवार है।

क्रमश: ..

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस

विमल कुमार

11 नवंबर का दिन विशेष है। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए प्रतिवर्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन (11 नवंबर) की स्मृति में ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। वैधानिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का प्रारंभ 11 नवंबर, 2008 से किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करने के साथ-साथ इस दिन संस्थानों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के ऐतिहासिक विकास और वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था के मूल प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। शिक्षाविद, शिक्षक और छात्र साक्षरता के महत्त्व तथा शिक्षा के विविध पहलुओं के प्रति अपने विचार प्रकट करते हैं। संगोष्ठियों, वर्कशॉप, पुस्तक प्रदर्शनी और व्याख्यान का आयोजन किया जाता है। स्कूलों में निबंध, क्विज, भाषण, पोस्टर मेकिंग जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि विश्व शांति और विकास के लिये शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देने के मकसद से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद करने का दिन है क्योंकि भारत में शिक्षा के विकास में मौलाना आज़ाद की उल्लेखनीय भूमिका रही है।

अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर, 1888 को मक्का शहर (सऊदी अरब) में हुआ। उनका वास्तविक नाम मुहिउद्दीन अहमद था। अपने पिता से आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आज़ाद मिश्र के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान जामिया अज़हर चले गए जहाँ उन्होंने प्राच्य शिक्षा प्राप्त की। आज़ाद को उर्दू, फ़ारसी, हिंदी, अरबी तथा अंग्रेज़ी भाषाओं में महारथ हासिल हुई।

आज़ाद अरब से प्रवास करके हिंदुस्तान आए तो कलकत्ता को अपनी कर्मभूमि बनाया। यहीं से उन्होंने अपनी पत्रकारिता और राजनीतिक जीवन का आरंभ किया। आज़ाद ने 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अलगाववादी विचारधारा को खारिज़ कर दिया। कलकत्ता से 1912 में 'अलहिलाल' नाम से एक साप्ताहिक निकाला। यह पहला सचित्र राजनैतिक साप्ताहिक था और इसकी मुद्रित प्रतियों की संख्या लगभग 52 हज़ार थी। इस साप्ताहिक में अंग्रेज़ों की नीतियों के विरुद्ध लेख प्रकाशित होते थे, इसलिये अंग्रेज़ी सरकार ने 1914 में इस साप्ताहिक पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद मौलाना ने 'अलबलाग़' नाम से दूसरा अख़बार प्रकाशित किया। यह अख़बार भी आज़ाद की अंग्रेज़ विरुद्ध नीति पर अग्रसर रहा।

मौलाना आज़ाद ने अख़बारों के द्वारा राष्ट्रीय, स्वदेशीय भावनाओं को जागृत करने की कोशिश की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 'पैग़ाम' और 'लिसान-उल-सिद्क़' जैसी पत्र-पत्रिकाएँ भी प्रकाशित की और विभिन्न अख़बारों से भी संबद्ध रहे जिनमें 'वकील' और 'अमृतसर' प्रमुख हैं।

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे। उन्होंने 'असहयोग आंदोलन', 'ख़िलाफ़त आंदोलन' और 'भारत छोड़ो' में भी हिस्सा लिया। गाँधी जी के अहिंसा के दर्शन से वह बहुत प्रभावित थे। गांधी के चिंतन और सिद्धांतों के प्रसार के लिये उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर भारत के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के विभाजन के घोर विरोधी और हिन्दू-मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पैरोकारों में से थे। मौलाना आज़ाद एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। 1940 और 1945 के बीच भी वे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने जेल की यातनाएं भी सही। एक सहयात्री के रूप में स्वाधीनता संग्राम में उनकी धर्मपत्नी ज़ुलेख़ा बेगम का योगदान भी अविस्मरणीय है।

बदले हालात में पाकिस्तान से खदेड़े जा रहे हैं अफगान शरणार्थी

मरिआना बाबर

इस हफ्ते अफगानिस्तान मेरे जेहन में छाया रहा। वास्तव में इस्लामाबाद में अफगानिस्तान सुर्खियों में रहा, भारत के विभिन्न शहरों में होने वाले क्रिकेट विश्व कप में अफगानिस्तानी क्रिकेट टीम के प्रदर्शन और काबुल स्थित तालिबानी शासन की चर्चा होती रही। भारत में खेले जा रहे विश्व कप शृंखला में अफगानिस्तान की अल्पज्ञात क्रिकेट टीम तब सुर्खियों में आई, जब उसने जुनून के साथ खेलकर पाकिस्तान और इंग्लैंड जैसे क्रिकेट चैंपियनों को पराजित कर दिया, हालांकि बीते मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेलने के बावजूद वह जीत दर्ज नहीं कर पाई।

दिलचस्प है कि इनमें से कई असाधारण अफगान खिलाड़ियों ने पहली बार बल्ला तब पकड़ा था, जब वे पेशावर में शरणार्थी शिविर में रह रहे थे। दक्षिण एशिया के अन्य मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी ज्यादातर लड़कों द्वारा क्रिकेट न केवल अभिजात क्लबों और खास मैदानों में, बल्कि लगभग हरेक मोहल्ले और गलियों में खेला जाता है। क्रिकेट की तरह दूसरा कोई भी खेल इतना लोकप्रिय नहीं है।

अफगानिस्तान पर सोवियत कब्जे के दौरान पेशावर में शरणार्थी शिविर ऐसे युवा अफगान लड़कों से भरे हुए थे, जो आपस में या पाकिस्तानी लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते थे। एक समय में पाकिस्तान ने दुनिया की सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी की मेजबानी की थी। ईरान के विपरीत पाकिस्तान में तीन लाख अफगान शरणार्थियों पर केवल शिविरों तक सीमित रहने पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, वे पूरे पाकिस्तान में यात्रा करते थे। काबुल के

विश्वविद्यालय में एक बार बैठक में प्रोफेसरों ने मुझे बताया कि कोई भी बता सकता है कि कौन-सा अफगान शरणार्थी पाकिस्तान या ईरान से लौटा है। %ईरान की तुलना में पाकिस्तान से लौटे शरणार्थियों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुंच प्राप्त हुई है।%

वास्तव में जब मैं 1990 के दशक में शोध कर रही थी, तो एक बुजुर्ग अफगान से मिली, जिन्होंने मुझसे कहा कि वे तभी अफगानिस्तान लौटेंगे, जब उनकी बेटियों को वहां पढ़ने का मौका मिलेगा। आज 2023 में भी तालिबान के कठोर शासन में अफगानिस्तान में लड़कियों को शिक्षा का हक नहीं है। दुनिया भर के मुल्कों ने तालिबान से आग्रह किया कि वे लड़कियों को शिक्षा की इजाजत दें, क्योंकि यह अफगानिस्तान की संस्कृति एवं परंपरा है तथा इस्लाम लड़कियों को शिक्षा से वंचित नहीं करता है। लेकिन वे किसी की नहीं सुनते।

अब पिछले एक महीन से पाकिस्तान में भी अफगान शरणार्थियों के लिए चीजें बदल गई हैं, जहां नई नीति के अनुसार, अवैध रूप से रहने वाला कोई भी विदेशी अब यहां नहीं रह सकता है। जिन लोगों को जबरन पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, उनमें से कई शिकायत कर रहे हैं कि अन्य तमाम समस्याओं के साथ एक समस्या यह भी है कि उनकी बेटियों को अफगानिस्तान में शिक्षा का हक हासिल नहीं है।

पाकिस्तान में अवैध अप्रवासियों में सबसे बड़ी संख्या अफगानों की है, खासकर सिंध के कराची जैसे शहरों में, जहां दूसरे मुल्कों के लोग भी रहते हैं। कराची अफगान शरणार्थियों एवं दूसरे मुल्कों के हजारों लोगों से भरी हुई है। जब ये अवैध अप्रवासी अपने मुल्क लौट रहे थे, तो पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा, %पाकिस्तान कोई अंतरराष्ट्रीय अनाथालय नहीं है।% शरणार्थियों एवं स्थानीय लोगों के बीच झगड़े हमेशा आर्थिक कारणों से होते रहे हैं। खैबर पख्तुनख्वा के मेरे गांव पीर पियाई में बीती सदी के अस्सी के दशक में अफगान शरणार्थियों का स्वागत किया गया था। उनका मजहब, भाषा, संस्कृति और परंपरा पाकिस्तानी पख्तूनों की तरह ही है। लेकिन जब हजारों शरणार्थी अपने साथ मवेशियों को लेकर आए, तो जल्दी ही पानी को लेकर झगड़ा होने लगा, क्योंकि इलाके में पानी की कमी थी। पेशावर जैसे बड़े शहरों में नौकरियां भी खतरे में थीं, क्योंकि अफगान जीवित रहने के लिए कोई भी नौकरी करने को तैयार थे और रोजगार बाजार में नौकरियां पर्याप्त नहीं थीं। इसके अलावा विभिन्न देशों एवं एजेंसियों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी जाने वाली विदेशी सहायता दशकों से बंद हो गई। ऐसे में तीन लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों का भरण-पोषण करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया। ये शरणार्थी विभिन्न चरणों में पाकिस्तान आए। पहले चरण में बीती सदी के अस्सी के दशक में सोवियत कब्जे के दौरान ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से शरणार्थी आए। बाद में मैंने अफगान शरणार्थियों के एक नए समूह का इंटरव्यू लिया, जिसमें डॉक्टर, शिक्षक जैसे उच्च शिक्षित लोग थे, जिन्हें पाकिस्तान में आसानी से नौकरी मिल जाती थी। अफगानिस्तान में दशकों तक युद्ध जारी रहने और यहां तक शांति काल में भी वहां से शरणार्थियों का आना बंद नहीं हुआ। कुछ लोग चिकित्सा सहायता के लिए भी आए, जिनमें से कुछ तालिबान के घायल लड़ाके थे।

पाकिस्तान से अवैध अफगानों को निकालने का फैसला एक दिन में नहीं लिया गया। पाकिस्तान वर्षों से काबुल से कहता रहा है कि अफगानों की सम्मान एवं गरिमा के साथ वापसी सुनिश्चित की जाए। पर जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को संरक्षण देना शुरू किया, जो पाकिस्तान में आतंकी हमले करते थे, तो नए सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा कि बस, अब बहुत हो चुका। टीटीपी के कई लड़ाके शरणार्थी शिविर में रहते थे और आसानी से उनमें शामिल हो गए। पाकिस्तान ने टीटीपी से बातचीत भी की थी, पर उनकी शर्तें पाकिस्तान के संविधान और कानून के खिलाफ थीं।

इस हफ्ते बलूचिस्तान के चमन शहर में भारी प्रदर्शन हुआ, जिसकी सीमा अफगानिस्तान से सटी हुई है। सीमा के दोनों तरफ से मांग हो रही थी कि पहले की तरह बिना पासपोर्ट और वीजा के एक-दूसरे मुल्क में प्रवेश की इजाजत मिले। इस मानसिकता को बदलना होगा और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बिना दस्तावेजों के यात्रा करने वालों पर प्रतिबंध लगाना होगा। अफगानिस्तान का कहना है कि उसे पाकिस्तानियों के बिना दस्तावेजों के आने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान राजी नहीं है। क्या ये अफगान बिना दस्तावेज के ईरान में प्रवेश कर सकते हैं? सीमा पर ईरानी सुरक्षा बल इतने सख्त हैं कि वे पहले गोली चलाते हैं, फिर सवाल पूछते हैं।

आज का इतिहास

1938 इस्मत इनोऊ तुर्की के दूसरे राष्ट्रपति बने।
1940 द्वितीय विश्व युद्ध-जर्मन सहायक क्रूजर अटलांटिस ने एसएस ऑटोमेडन के शीर्ष गुप्त दस्तावेजों पर कब्जा कर लिया, जो बाद में युद्ध में प्रवेश करने के जापान के फैसले को प्रभावित करेगा।
1942 द्वितीय विश्व युद्ध-द अल्मी ने मिस्र के अल अलमीन के दूसरे युद्ध में एक्सिस को हराया, स्वेज नहर पर नियंत्रण के एक्सिस आशाओं को समाप्त करके उत्तरी अफ्रीकी अभियान में ज्वार को बदल दिया और इस तरह ईस्टमेड पूर्वी तेल क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त की।
1953 कैम्ब्रिज विवि में पहली बार %पोलियो वायरस% की पहचान हुई और उसका चित्र लिया।
1960 वियतनाम के राष्ट्रपति न्गो दीन्ह दीम के खिलाफ सेना की तख्तापलट की कोशिश के बाद डिएम को गलत तरीके से सुधार का वादा करने के बाद कुचल दिया गया, जिससे वफादारों ने उसे बचाया।
1965 प्रधान मंत्री इयान स्मिथ के नेतृत्व में दक्षिणी रोडेशिया, यूनाइटेड किंगडम से एकतरफा घोषित होकर रोडेशिया बन गया।
1975 ऑस्ट्रेलिया में एक संवैधानिक संकट के दौरान, गवर्नर-जनरल जॉन केर ने प्रधान मंत्री गफ व्हिटलाम की सरकार को खारिज कर दिया और दोहरे विघटन चुनाव के लिए संसद को भंग कर दिया।
1982 इजरायल के सैन्य मुख्यालय में गैस विस्फोट में 60 लोगों की मौत हुई।
1985 एड्स थीम पर आधारित पहली टीवी फिल्म %एन अर्ली फ्रोस्ट% अमेरिका में प्रदर्शित की गई।
1992 चर्च ऑफ इंग्लैंड वोट देने के लिए महिलाओं को पुजारी बनने की अनुमति दी गयी।
1999 ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स से अधिकांश वंशानुगत साथियों को हटाते हुए हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक्ट को शाही स्वीकृति प्रदान की गई।
2000 कपहून, ऑस्ट्रिया स्थित एल्पाइन सुरंग में एक केबल कार में आग लगने से 155 की मौत हुई।

क्या छत्तीसगढ़ के चुनाव को त्रिशंकु बना पाएंगी क्षेत्रीय पार्टियां ?

रोहित मिश्र

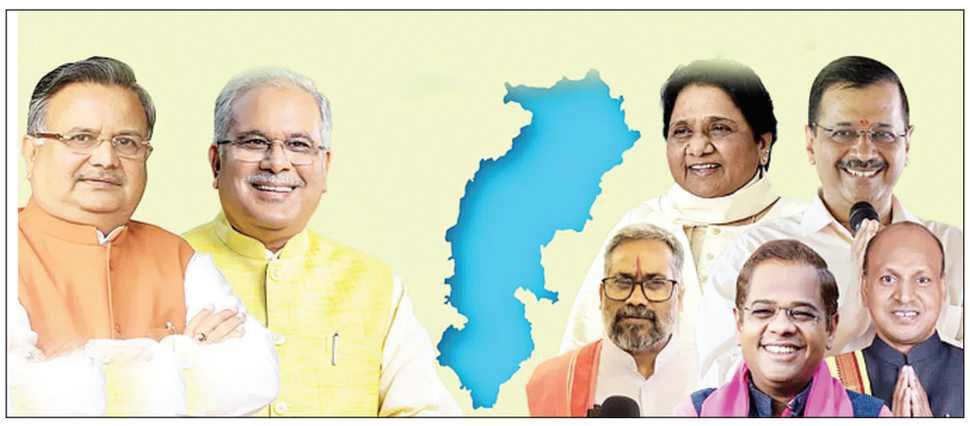

2018 के चुनाव में जोगी कांग्रेस, बसपा और सीपीआई के गठबंधन को 11 फीसदी वोट मिले थे। पांच सीटें अजीत जोगी की पार्टी को और दो सीटें बसपा को मिलीं थीं। इस बार राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। अजीत जोगी नहीं रहे। अजीत जोगी के साथ कांग्रेस छोड़कर आए बहुत सारे नेता या तो कांग्रेस में लौट गए या फिर उन्होंने कोई दूसरा ठिकाना तलाश लिया। बसपा इस बार जोगी की पार्टी के साथ नहीं है। आम आदमी पार्टी सिर्फ वोट काटने की हैसियत में दिख रही है। वह कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट काट सकती है लेकिन वह इन दोनों पार्टियों का कोई बड़ा नुकसान करेगी ऐसा नहीं कह सकते। बस्तर के भानुप्रतापपुर के उपचुनाव में 22 हजार वोट पाकर चर्चाओं में आने वाली हमर राज पार्टी भी एक ऐसी दावेदार है। इस पार्टी के प्रमुख अरविंद नेताम एक दर्जन से अधिक सीटों पर पार्टी के दबदबे का दावा करते रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से बनी जोहार छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने प्रदेश की 46 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं।

राज्य की स्थापना के बाद से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ का चुनाव दो ध्रुवों के बीच बंटा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच केंद्रित रहने वाली इस लड़ाई में तीसरी ताकतों ने सेंध लगाने की कोशिशें तो जरुर कीं लेकिन उन्हें उस तरह की सफलता नहीं मिली कि वह पार्टियां इतनी सीटें बटोर लें कि सीटों के लिहाज से इस छोटे प्रदेश में वह किंग मेकर बन सकें या किसी प्रकार के मोल-भाव की स्थितियों में आ जाएं। 2003 के पहले विधानसभा चुनावों से लेकर 2018 के विधानसभा चुनावों तक जाति या किसी समाज के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली यह क्षेत्रीय पार्टियां सीट पाने के मामले में अब तक कोई बड़ी लकीर नहीं खींच सकी हैं। ना ही इन पार्टियों का प्रदर्शन इतना महत्वपूर्ण रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के माथे पर कोई राजनीतिक शिकन पड़े। पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये पार्टियां खेल बिगाड़ने की हैसियत नहीं रखतीं। छोटी-छोटी मार्जिन से होने वाली चुनावी जीत-हार में इन पार्टियों को मिला वोट कई बार निर्णायक साबित होता रहा है।

अजीत जोगी ने जब 2016 में कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाई थी तब इस बात के कयास तेजी से लगने शुरू हुए थे कि क्या इस बार छत्तीसगढ़ में त्रिशंकु के हालात होंगे। 2018 के चुनावों में पहली बार ऐसा लगा था कि राज्य में बीजेपी या कांग्रेस स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाएंगी। खुद अजीत जोगी अपनी सभाओं में इस बात का बारम्बार दावा करते थे कि बिना उनके राज्य में किसी की सरकार नहीं बनेगी। अजीत जोगी की पार्टी ने बसपा के साथ समझौता किया। चुनाव में उनकी पार्टी को पांच और बसपा को दो सीटें मिलीं। यह सात सीटें महत्वपूर्ण हो सकती थीं लेकिन कांग्रेस को मिले प्रचंड बहुमत के बाद यह सात सीटें औचित्यहीन हो गईं।

अब छत्तीसगढ़ फिर से चुनावों के समर में हैं। बस्तर संभाग की बीस सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बची 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट पड़ने हैं। इस बार अजीत जोगी नहीं हैं। उनके पुरानी राजनीतिक पार्टनर बसपा का गठबंधन किसी और दल के साथ है। अमित जोगी राज्य की कुछ सीटों को छोड़कर करीब-करीब सभी पर ताल ठोंक रहे हैं। आम आदमी पार्टी दूसरी बार राज्य में चुनाव लड़ रही है। जाति और समाज की राजनीति करने वाले कुछ नए-पुराने खिलाड़ी नए दावों के साथ चुनावी समर में हैं। आइए समझते हैं कि क्या ये पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस की पारंपरिक सत्ता को चुनाती देते हुए इतनी सीटें बटोर सकती हैं कि यह दोनों राष्ट्रीय दल चुनाव के बाद इनके समर्थन के मोहताज हो जाएं। क्या राज्य में किसी भी तरह के त्रिशंकु के हालात बन सकते हैं?

अजीत जोगी के द्वारा बनाई गई पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इस बार 84 सीटों पर लड़ रही है। खुद अमित जोगी पाटन सीट पर मुख्यमंत्री के खिलाफ ताल ठोंक रहे हैं। 2018 के चुनाव में जोगी कांग्रेस, बसपा और सीपीआई के गठबंधन को 11 फीसदी वोट मिले थे। पांच सीटें अजीत जोगी की पार्टी को और दो सीटें बसपा को मिलीं थीं। इस बार राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। अजीत जोगी नहीं रहे। अजीत जोगी के साथ कांग्रेस छोड़कर आए बहुत सारे नेता या तो कांग्रेस में लौट गए या फिर उन्होंने कोई दूसरा ठिकाना तलाश लिया। बसपा इस बार जोगी की पार्टी के साथ नहीं है। इन बदले हुए राजनीतिक हालातों पर जोगी की पार्टी किस तरह चुनाव का प्रबंधन कर रही है इस पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समालोचक दिवाकर मुक्तिबोध कहते हैं कि पिछले चुनाव में अजीत जोगी ऐसा माहौल रचने में सफल रहे थे जहां दोनों पार्टियों को यह लग रहा था कि अजीत कुछ सीटें जीतने में सफल हो सकते हैं। इस बार का माहौल ऐसा नहीं है।

राजनीतिक गलियारों में अमित जोगी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप है। टिकट देने में भी उन्होंने सात साल पुरानी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बजाय बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेताओं को चुना है। जिसमें ज्यादातर कांग्रेस के बागी हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां वह कांग्रेस को असहज तो कर सकते हैं लेकिन वह चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण असर डाल पाएंगे ऐसा होता नहीं दिख रहा है। वरिष्ठ टीवी पत्रकार बरुण सखाजी इसमें कुछ बातें और जोड़ते हैं। वह कहते हैं कि अमित जोगी ने खुद पाटन सीट से लड़कर चुनाव को रोचक तो बना दिया है लेकिन पूरे प्रदेश में वह कोई माहौल बना पाए हैं ऐसा होता नहीं दिखता। ज्यादातर प्रत्याशी मुख्य लड़ाई से बाहर हैं। रेणु और रिचा जोगी की सीट खुद भी त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी है। हालांकि उन्हीं स्थिति बाकी उम्मीदवारों से बेहतर है।

कांशीराम के जमाने से ही राज्य में जड़े जमाने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार फिर से छत्तीसगढ़ में ताल ठोंक रही है। बीते चुनाव में अजीत जोगी की पार्टी से गठबंधन करने वाली बसपा इन चुनावों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ एलांयस में है। बसपा 58 तो गोडंवाना गणतंत्र पार्टी 32 सीटों पर लड़ रही है। बसपा का प्रभाव हमेशा से ही बिलासपुर संभाग में रहा है। प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां बसपा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध कहते हैं कि बसपा का आधार दलित है। पिछले दो चुनावों से उसकी कोशिश उस दलित वोट में आदिवासी वोटों को जोड़ने की है। 2018 के चुनावों में उसने अजीत जोगी की पार्टी से एलायंस किया। उसे दो सीटें मिलीं और कई सीटों पर उसके वोटों में भी इजाफा हुआ।

इस बार उसने राजनीतिक पार्टनर बदल दिया है। आदिवासी वोटों में पैठ का दावा करने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ उसका गठबंधन है। अभी तक का जो माहौल राज्य में बन रहा है उसमें इस गठबंधन का प्रभाव सीमित सीटों पर दिख रहा है। हो सकता है कि कई सीटों पर वह मुख्य पार्टियों का नुकसान करे जिसमें कांग्रेस के नुकसान की संभावना ज्यादा है, लेकिन यह कहना मुश्किल होगा कि इस गठबंधन की सीटें इतनी आएंगी कि वह बीजेपी या कांग्रेस को असहज करे। दिवाकर मुक्तिबोध इसकी वजह स्थानीय नेतृत्व का ना होना बताते हैं। राज्य में बसपा ऐसा कोई नेता विकसित नहीं कर पाई जो कुछ सीटों पर अपने प्रभाव को लगातार बनाकर रख पाया हो। जिन सीटों पर दलितों की संख्या कम है उन सीटों पर बसपा का कोई प्रभाव नहीं है। इसी तरह शहरी सीटों में भी बसपा का प्रभाव नहीं है। हीरा सिंह मरकाम के निधन के बाद यही हाल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का है।

आम आदमी पार्टी दूसरी बार छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में ताल ठोंक रही है। आम आदमी पार्टी बीते दस बरस में राज्य में सक्रिय रही है। अरविंद केजरीवाल ने यहां पर एक राष्ट्रीय अधिवेशन भी किया। दस प्वाइंट का घोषणा पत्र भी जारी किया। अब जब चुनाव अपने पीक पर हैं तो वह आम आदमी पार्टी किस तरह से चुनावों को लड़ रही है इस सवाल पर दिवाकर मुक्तिबोध कहते हैं कि अभी तक के ट्रेंड को देखकर लग रहा है आम आदमी पार्टी किसी भी सीट को अपने पक्ष में त्रिकोणीय बनाने में सफल नहीं दिख रही है। अपवाद को छोड़ दें तो वह चुनाव के समीकरणों से वह करीब-करीब बाहर है।

वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई भी कुछ ऐसी ही राय रखते हैं। रवि कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ वोट काटने की हैसियत में दिख रही है। वह कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट काट सकती है लेकिन वह इन दोनों पार्टियों का कोई बड़ा नुकसान करेगी ऐसा नहीं कह सकते। छत्तीसगढ़ की चुनावी राजनीति को समझने वाले राजनीतिक टीकाकार मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने चुनावों से ठीक पहले ही अपने रफ्तार सुस्त कर दी है। यह उनका राजनीतिक गेम प्लान भी हो सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता बहुत सक्रिय नहीं हैं। केजरीवाल भी अभी तक सिर्फ एक बार ही चुनाव प्रचार के लिए आए हैं।

इन दलों के अलावा कुछ और छोटी पार्टियां भी छत्तीसगढ़ के चुनावों में दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं। बस्तर के भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में 22 हजार वोट पाकर चर्चाओं में आने वाली हमर राज पार्टी भी एक ऐसी दावेदार है। इस पार्टी के प्रमुख अरविंद नेताम एक दर्जन से अधिक सीटों पर पार्टी के दबदबे का दावा करते रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से बनी जोहार छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने प्रदेश की 46 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। वह 44 बिंदुओं पर अपनी पार्टी का घोषणा पत्र भी लॉन्च कर चुके हैं। इन छोटी पार्टियों की कोशिशों पर टीवी पत्रकार बरुण सखाजी कहते हैं कि उपचुनावों में यह पार्टियां जरुर दमखम दिखाती हैं लेकिन मुख्य चुनाव में जब चुनाव अपने निर्णायक मुकाम पर पहुंच जाता है तो उस दौड़ में यह पार्टियां पीछे छूटने लगती हैं। अभी के राजनीतिक वातावरण को देखकर यह लगता है कि यह पार्टियां भले खुद सीटें ना जीते लेकिन वह दोनों बड़ी पार्टियों का नुकसान जरूर कर सकती हैं। इसमें ज्यादा नुकसान कांग्रेस का होना तय माना जा रहा है।

2018 के चुनाव परिणाम को देखा जाए तो कांग्रेस का वोट शेयर 43 प्रतिशत था और बीजेपी का 32 प्रतिशत। बीजेपी और कांग्रेस के वोट में दस प्रतिशत का अंतर था। लेकिन मत प्रतिशत का यह अंतर सीटों में प्रतिबिंबित नहीं हुआ। कांग्रेस 68 सीटों पर चुनाव जीती और बीजेपी 15 सीटों पर अटक गई थी। उधर जोगी कांग्रेस,बसपा, सीपीआई के गठबंधन को 11 प्रतिशत वोट मिले थे। बाकी अन्य छोटे-छोटे दलों का वोट प्रतिशत भी जोड़ लिया जाए तो यह करीब 14 प्रतिशत पहुंचता है। इसमें यदि निर्दलीय वोटों को भी जोड़ लें तो यह 23 प्रतिशत होता है। राजनीतिक टीकाकार मानते हैं कि इस बार इस वोट प्रतिशत में कुछ इजाफा हो सकता है। भले ही यह पार्टियां इसे सीट में कन्वर्ट ना कर सकें लेकिन इस चुनाव में उनका मत प्रतिशत बढ़ा हुआ नजर आ सकता है।

राहुल का राजस्थान न जाना क्या है पर्दे के पीछे की कहानी

अंकित सिंह

राजस्थान में चुनाव की तारीखों की घोषणा के एक महीने बाद, और 25 नवंबर को मतदान होने में लगभग एक पखवाड़ा बचा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभी तक राज्य में एक रैली नहीं की है। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के बाद, राहुल राजस्थान के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। जबकि पार्टी नेताओं का कहना है कि, प्रियंका गांधी वाड्रा और खड़गे के साथ, राहुल दिवाली के बाद राजस्थान पर ध्यान केंद्रित करेंगे और यहां कई रैलियां करेंगे, उनकी अनुपस्थिति से कुछ बातें हो रही हैं। राहुल मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए देर से पहुंचे हैं। चुनाव में जब एक सप्ताह से भी कम समय बचा है तब राहुल पहुंचे हैं। 9 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद से, खड़गे ने दो रैलियां की हैं- 16 अक्टूबर को बारां में, जो पार्टी के महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) अभियान से जुड़ी थी, और दूसरी 6 नवंबर को जोधपुर में, जिस दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना नामांकन दाखिल किया। हालाँकि, राजस्थान में राहुल की आखिरी वार 23 सितंबर को जयपुर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन (पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक) थी, जहाँ खड़गे भी मौजूद थे। और उससे पहले 9 अगस्त को मानगढ़ धाम में रैली थी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि चूंकि अन्य राज्यों में राजस्थान से पहले मतदान हो रहा है, इसलिए राहुल उन राज्यों में कार्यक्रम कर रहे हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का अनुमान है कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत की बेहतर संभावना दिख रही है, और इसलिए उन दो राज्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। राहुल ने सितंबर में दिल्ली में एक कार्यक्रम में यह कहते हुए खुद इस धारणा में योगदान दिया है- अभी, हम शायद तेलंगाना में जीत रहे हैं, हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, हम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं। राजस्थान, हम बहुत करीब हैं और हमें लगता है कि हम जीतने में सक्षम होंगे। कांग्रेस नेता मानते हैं कि राजस्थान की जीत में कम विश्वास वाला यह वोट वह नहीं था, जिसकी उन्हें जरूरत थी। जबकि राज्य ने पिछले 30 वर्षों से चुनाव के बाद सत्ताधारी को सत्ता से बाहर कर दिया है, कांग्रेस ने भाजपा के भीतर विभाजन को देखते हुए इस प्रवृत्ति को उलटने की उच्च उम्मीद के साथ शुरुआत की। हालाँकि, चुनावों के समय में, भाजपा को एक जुटता दिखाई दे रही है।

मध्यप्रदेश में प्रियंका के रोड शो से कांग्रेसी नेता नाखुश

राहुल संपाल

कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को इंदौर में थीं। प्रियंका ने शहर की सबसे हॉट सीट क्षेत्र क्रमांक एक में रोड शो किया। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के समर्थन में हुआ ये रोड शो बहुत जल्दी खत्म हो गया। महज 45 मिनट चले इस रोड शो को लेकर स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ता नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस सीट से कांग्रेस के संजय शुक्ला विधायक हैं, उन्होंने क्षेत्र में अच्छा काम किया है। गिनाते-गिनाते रात कम पड़ जाए। अगर कार्यकर्ताओं के साथ बड़े नेता भी क्षेत्र में ज्यादा नजर आएंगे, तो जीत में आसानी होगी। स्टार प्रचारकों से हमारी मांग है कि रोड शो में ज्यादा समय दें ताकि क्षेत्र में माहौल बन सके और कांग्रेस पार्टी को चुनाव में ज्यादा फायदा मिल सके।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार शाम 5.30 बजे विधानसभा क्षेत्र क्रंमांक एक स्थित टिगरिया रोड स्थित गणेश तिराहा से रोड शो शुरू किया। 3.50 किमी के हिस्से में हुए रोड शो में करीब 120 मंचों से प्रियंका का स्वागत हुआ। जिस वाहन में प्रियंका सवार थीं उसमें कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के साथ उनकी पत्नी अंजली शुक्ला भी साथ थीं। जिस वाहन पर प्रियंका सवार थीं उसी वाहन से उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। प्रियंका ने कहा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। साथ ही सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाए दीं। प्रियंका ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप गुडागर्दी से मुक्ति चाहते हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाएं।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रियंका गांधी के रोड शो पर निशाना साधते हुए कहा कि

मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, पर एकदम फ्लॉप शो था। जितनी जनता नहीं थी उसमें, उससे ज्यादा पुलिस थी। और उनके व्यवहार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लोग उन्हें देखने आते हैं, लेकिन यहां एक नंबर की जनता उन्हें देखने भी नहीं आई, इसका मुझे आश्चर्य हुआ। विजयवर्गीय ने कहा कि उन्होंने हनुमान जी को कभी माना नहीं, राम चरित्र मानस को कभी माना नहीं, अब उनको चुनाव जीतने के लिए हनुमानजी याद आ रहे हैं। हनुमानजी अच्छी तरीके से जानते हैं कि असली कौन है, और नकली कौन है, ये चुनावी हिंदू हैं।

इंदौर की क्षेत्र क्रमांक एक विधानसभा क्षेत्र शहर की सबसे चर्चित सीटों में से है। भाजपा ने यहां से शहर के कद्दावर नेता और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा है। जबकि कांग्रेस ने वर्तमान विधायक संजय शुक्ला पर फिर विश्वास जताया है। कैलाश विजयवर्गीय के चुनावी मैदान में उतरने के बाद से ही इस सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। विजवर्गीय खुद क्षेत्र में नुक्कड़ सभा से लेकर घर-घर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि शुक्ला भी मैदान में डटे हुए हैं। उनके समर्थन में कई स्टार प्रचारक क्षेत्र में छोटी सभाएं और रोड़ शो कर रहे हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के लिए विधानसभा क्षेत्र नंबर-1 जीतना इतना आसान नहीं है। पिछले 10 सालों से प्रदेश की राजनीति से कैलाश विजयवर्गीय दूर हैं। दूसरी तरफ, वर्तमान में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला विधायक हैं। वे ब्राह्मण समाज से आते हैं। ब्राह्मण वोट की विधानसभा क्षेत्र नंबर-1 में बड़ी भूमिका है। माना जा रहा है कि जातीय समीकरण साधना भी विजयवर्गीय के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी।

विजयवर्गीय कह चुके हैं कि यह चुनाव मैं नहीं यहां के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह एक लाख वोट से मुझे जिताएंगे। उन्हें पार्टी ने कई जिम्मेदारियां दे रखी हैं। उन्हें मध्यप्रदेश की करीब 90 सीटों पर दौरा करना है। हाल ही में कैलाश ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि मेरी भूमिका पिछले 10 साल से केंद्र में है। मैं चुनाव लड़ाने के काम करता हूं, चुनाव लड़ने का नहीं लेकिन पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। पार्टी का सिपाही हूं तो पार्टी के आदेश का पालन करूंगा। लेकिन, अब गली-मोहल्ले में वोट मांगने की आदत नहीं है। अब तो हम बड़े नेता हो गए हैं।

कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने भी प्रतिक्रिया दी थी। शुक्ला ने कहा था कि कैलाश जी मुझे हलुआ नेता समझते हैं। इसलिए मेरे सामने चुनाव लड़ने आए हैं। वे हेलीकॉप्टर नेता हैं। जनता हेलीकॉप्टर की तरह ही उड़ा देगी। मैं इस देश के नंबर वन नेता कैलाश को एक लाख वोट से चुनाव हराऊंगा।

रोड शो में प्रियंका गांधी के साथ जीप में कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला, पार्षद विनितिका यादव और शिवम यादव सवार थे। इनके अलावा जीप पर चढ़ने का प्रयास शहर अध्यक्ष सुरीजत सिंह चड्ढा, कार्यवाहक अध्यक्ष गोलू अग्निहोत्री, वरिष्ठ नेता शोभा ओझा आदि बड़े नेताओं ने किया। लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने इन नेताओं को जीप पर नहीं चढ़ने नही दिया। इस पर यह नेता पैदल-पैदल चलने लगे।

राजस्थान में किसकी लहर, ये 10 सीटें तय करेंगी चुनावी परिणाम

अंकित सिंह

राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक जबरदस्त तरीके से गर्म है। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती आई है लेकिन अशोक गहलोत का नेतृत्व में कांग्रेस इस परिपाटी को बदलने की कोशिश में है। हालांकि, सत्ता विरोधी लहर उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं, भाजपा भी राज्य में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, जल जीवन मिशन जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। इन सब के बीच आज हम आपको ऐसे कुछ सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर सभी की निगाहें हैं।

सरदारपुरा

यह सीट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जानी जाती है और जोधपुर क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह कांग्रेस का गढ़ है जहां पार्टी 1998 के बाद से एक भी विधानसभा चुनाव नहीं हारी है। उसी साल, गहलोत वहां से उपचुनाव में चुने गए और तब से हारे नहीं हैं। आखिरी बार भाजपा ने यहां जीत का स्वाद 1993 में चखा था जब एक और गहलोत - राजेंद्र गहलोत - जीते थे। 2018 में अशोक गहलोत को 63 फीसदी से ज्यादा वोट मिले और उन्होंने बीजेपी के संभू सिंह को 45,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया. इस बार बीजेपी ने गहलोत के खिलाफ महेंद्र सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा है।

झालरापाटन

राज्य के दक्षिणी भाग की यह विधानसभा सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका प्रतिनिधित्व पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान में भाजपा की सबसे ताकतवर नेता - वसुंधरा राजे सिंधिया करती हैं। जिस तरह सरदारपुरा सीट पर 1998 से गहलोत का कब्जा है, उसी तरह राजे 2003 से इस सीट से जीतती आ रही हैं। आखिरी बार कांग्रेस ने झालरापाटन सीट 1998 में जीती थी। पिछले चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजे ने कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को 35,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। उन्हें कुल पड़े वोटों में से 54 फीसदी वोट मिले। वह स्थानीय लोगों की पसंदीदा हैं और चाहे कोई भी सत्ता में आए, इस सीट से उनके जीतने की संभावना बहुत अधिक रहती है।

टोंक

जयपुर से 100 किलोमीटर दूर स्थित टोंक विधानसभा सीट राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का क्षेत्र है। 2020 में अशोक गहलोत के साथ अपने राजनीतिक तनाव के बावजूद, पायलट को टोंक में %मिट्टी का बेटा% माना जाता है। हालाँकि, गहलोत या राजे के विपरीत, वह 2018 से केवल इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2018 में, भाजपा ने अल्पसंख्यक उम्मीदवार यूनुस खान को मैदान में उतारा, जिन्हें पायलट ने 50,000 से अधिक वोटों के भारी अंतर से हराया। इस बार बीजेपी ने पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता को मैदान में उतारा है। उन्होंने टोंक में 2013 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के बागी सऊद सईदी को हराकर जीता था - जो अब पायलट के वफादार माने जाते हैं। खास बात यह भी है कि बीजेपी ने गुर्जरों को लुभाने के लिए दिल्ली से अपने सांसद रमेश बिधूड़ी को एक महीने से ज्यादा समय तक यहां तैनात रखा है।

विद्याधर नगर

भाजपा सांसद दीया कुमारी को इस सीट से मैदान में उतारने के बाद से यह सीट रातों-रात मशहूर हो गई। ऐसी अटकलें हैं कि वह राजस्थान बीजेपी का %नया चेहरा% होंगी और अगर बीजेपी जीतती है तो वह अगले मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हैं। यह विधानसभा क्षेत्र जयपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो दीया कुमारी का गृह क्षेत्र भी है। वह जयपुर राजघराने की राजकुमारी थीं। भाजपा 2008 से यह सीट जीत रही है।

लक्ष्मण गढ़

जयपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर, सीकर जिले में स्थित, लक्ष्मण गढ़ कांग्रेस के राजस्थान अध्यक्ष और इस समय राजस्थान के सबसे चर्चित राजनीतिक व्यक्तित्व - गोविंद सिंह डोटासरा का गृह क्षेत्र है। गहलोत सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा 2008 से यहां से जीत रहे हैं। आखिरी बार बीजेपी 2003 में जीती थी जब केशर देव विजयी हुए थे। लेकिन इससे पहले भी, कांग्रेस ने यह सीट तीन बार और जीती।

सवाई माधोपुर

जयपुर के नजदीक यह सीट अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राज्य में पार्टी के भ्रष्टाचार विरोधी चेहरे किरोड़ी लाल मीणा को दी जा रही है। 1998 से सवाई माधोपुर में कांग्रेस और भाजपा के विधायक बारी-बारी से निर्वाचित होते रहे हैं। मीना ने 2003 में यह सीट जीती थी। 2013 में यहां से बीजेपी की विद्याधर नगर उम्मीदवार दीया कुमारी ने जीत हासिल की थी। पिछली बार कांग्रेस के दानिश अबरार ने बीजेपी उम्मीदवार को 25,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराकर यह सीट जीती थी। 2018 में बीजेपी उम्मीदवार मीना समुदाय से थे।

नाथद्वारा

यह सीट कटुतापूर्ण खींचतान से एक अजीब प्रस्थान के साथ टाइटन्स के टकराव का गवाह बनने जा रही है। एक तरफ, कांग्रेस के पुराने योद्धा सीपी जोशी हैं - जो मौजूदा विधायक भी हैं - जिनकी ज़मीन पर साख है। दूसरी ओर, भाजपा के विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं - जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। ऐसा 30 साल बाद हुआ है जब महाराणा प्रताप के परिवार से कोई राजनीति में आया है। नाथद्वारा मेवाड़ क्षेत्र का हिस्सा है। भाजपा ने विश्वराज सिंह मेवाड़ को मैदान में उतारकर क्षेत्र के उन राजपूतों तक पहुंचने की कोशिश की है।

झोटवाड़ा

जयपुर के बाहरी इलाके में स्थित यह सीट तब से प्रमुखता से बढ़ गई है जब से जयपुर ग्रामीण से मौजूदा भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को यहां से लड़ने के लिए कहा गया है। पिछली बार कांग्रेस ने यह सीट जीती थी जब लालचंद कटारिया ने बीजेपी के राजपाल सिंह शेखावत को हराया था। शेखावत ने 2008 और 2013 में इस सीट से जीत हासिल की थी। राजपाल सिंह शेखावत और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दोनों राजपूत हैं। हालांकि, यहां टिकट को लेकर भाजपा में विरोध भी है जिसे कम करने की कोशिश हो रही है।

चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ एक बार फिर राजपूत आक्रोश का गवाह बन रहा है। इधर, भाजपा ने नरपत सिंह राजवी को समायोजित करने के लिए अपने दो बार के विधायक चंद्रभान सिंह को हटा दिया है। घटनाओं के एक अनोखे मोड़ में, चंद्रभान सिंह ने निर्दलीय के रूप में लड़ने का फैसला किया है। पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए चंद्रभान सिंह को 53.41 फीसदी वोट मिले थे।

हवामहल

जयपुर शहर के मध्य में स्थित हवा महल अपने स्थान के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस सीट का नाम जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल के नाम पर रखा गया है। इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होगा। ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने यहां से सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के मंत्री महेश जोशी को टिकट नहीं दिया है और उनकी जगह आरआर तिवारी को मैदान में उतारा है। भाजपा, जिसने यहां से भगवाधारी पीठाधीश्वर स्वामी बालमुकुंद आचार्य को अपना उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस की स्थिति का फायदा उठाने की उम्मीद कर रही है।

सुमित्रा साहू

कभी लोकतंत्र के खिलाफ लड़ने वाली महिला अब लोकतंत्र की सुरक्षा में तैनात

राज्य में नक्सलियों ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने उत्पात मचाने की भी कोशिश की। सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में चार सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, तथा जिले के टोंडामरका शिविर के करीब नक्सलियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में सीआरपीएफ का एक कमांडो घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नारायणपुर, बीजापुर और कांकेर जिलों में नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलीबारी भी हुई। इन घटनाओं में सुरक्षाबलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा की शेष 70 सीटों पर दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। तीन दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में मंगलवार को नारायणपुर जिले के हजारों मतदाताओं के साथ सुमित्रा साहू ने भी मतदान किया। सुमित्रा वह महिला है जो कभी लोकतंत्र के खिलाफ लड़ती थी लेकिन आज वह लोकतंत्र की सुरक्षा में तैनात है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। मतदान में 20 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 40,78,681 मतदाताओं में से 71.11 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया। इन सीटों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली हजारों महिलाओं में से एक सुमित्रा भी है। सुमित्रा ने नारायणपुर निर्वाचन क्षेत्र में अपना वोट डाला। वह 2018 में नक्सलवाद छोड़कर पुलिस में शामिल हुई है। सुमित्रा (34) ने 'पीटीआई–भाषा' को बताया कि वह नारायणपुर में माओवादियों की आमदई एरिया कमेटी में कमांडर के रूप में सक्रिय थी और दिसंबर 2018 में उन्होंने नक्सली संगठन छोड़ दिया था।

सुमित्रा ने कहा, ''मैं जनवरी 2019 में पुलिस बल में शामिल हुई। मुझे खुशी है कि मैंने पहली बार वोट दिया।'' नारायणपुर जिले के कड़ेनार गांव की निवासी सुमित्रा साहू 2004 में माओवादियों की सांस्कृतिक शाखा चेतना नाट्य मंडली के सदस्य के रूप में नक्सलवाद में शामिल हुई थी। उसे तत्कालीन पूर्वी बस्तर डिवीजन सचिव उर्मिला ने नक्सल आंदोलन में भर्ती किया था। नक्सल आंदोलन से जुड़ने के बाद सुमित्रा को संसदीय, विधानसभा और पंचायत चुनावों के दौरान माओवादियों द्वारा किए गए बहिष्कार के आह्वान का प्रचार करने का काम सौंपा जाता था। वह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से माओवादी विचारों का प्रचार करती थी। बाद में उसे माओवादियों की आमदई एरिया कमेटी में कमांडर का पद मिला। सुमित्रा ने बताया, अपने छह–सात सहयोगियों के पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाने और कड़ेनार गांव में पुलिस शिविर स्थापित होने के बाद दिसंबर 2018 में मैंने नक्सलवाद छोड़ दिया और 2019 में पुलिस में शामिल हो गई।

शुरुआत में मैंने गोपनीय सैनिक (गुप्त सैनिक) के रूप में कार्य किया और बाद में आरक्षक के रूप में पदोन्नत हुई। सुमित्रा ने आज पहली बार मतदान किया। लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने को लेकर सुमित्रा उत्साहित थी। उन्होंने कहा, यह गर्व का क्षण है। कभी लोकतंत्र के खिलाफ हथियार उठाया अब सुरक्षा बल में शामिल होकर लोकतंत्र की सुरक्षा में तैनात हूं। छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों में मंगलवार को पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया गया, जहां 71.11 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले चरण में 25 महिला उम्मीदवारों समेत 223 उम्मीदवार हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 12 विधानसभा क्षेत्रों वाले बस्तर संभाग में शांतिपूर्ण मतदान के लिए लगभग 60 हजार जवानों को तैनात किया गया। जिनमें से 40 हजार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के और 20 हजार राज्य पुलिस के जवान हैं। उन्होंने बताया कि पहले चरण के मतदान के लिए लगभग एक लाख सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए।

राज्य में नक्सलियों ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने उत्पात मचाने की भी कोशिश की। सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में चार सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, तथा जिले के टोंडामरका शिविर के करीब नक्सलियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में सीआरपीएफ का एक कमांडो घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नारायणपुर, बीजापुर और कांकेर जिलों में नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलीबारी भी हुई। इन घटनाओं में सुरक्षाबलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा की शेष 70 सीटों पर दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। तीन दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी।

हैट्रिक को बेताब कक्का, पाटन में भतीजा और जोगी बने राह का कांटा

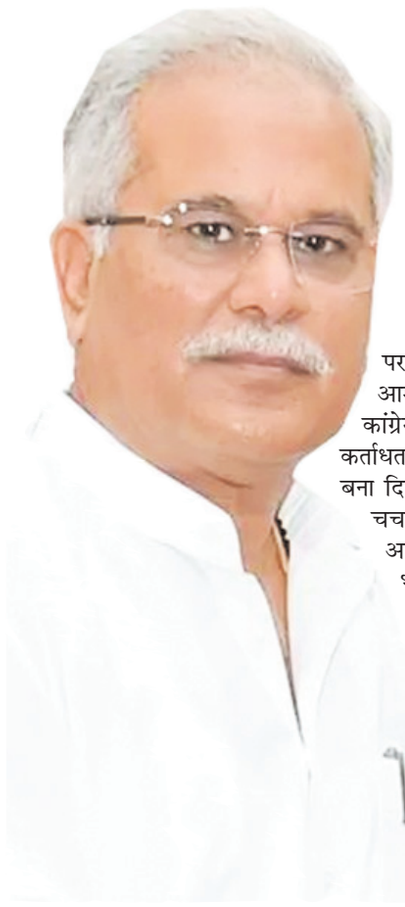

दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री कका व सांसद भतीजे की आमने-सामने की लड़ाई में कूदे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़-जोगी (जेसीसीजे) के कर्ताधर्ता अमित जोगी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। प्रदेश की सबसे हॉट सीट की चर्चा हर जगह है पर स्थानीय जनता असमंजस में है कि कक्का को चुनें या भतीजे को? असमंजस यह कि कक्का जीते तो सरकार बनने पर मुख्यमंत्री बनेंगे पर भतीजे का क्या? वहीं, अमित जोगी के यहां से मैदान में उतरने की चर्चा तो खूब है पर उनकी पार्टी की सरकार बनाने की लड़ाई में असरदार भूमिका न होने से जनता में विशेष दिलचस्पी नहीं।

पाटन सीट से सीएम भूपेश बघेल के सामने भाजपा के टिकट पर दुर्ग के सांसद विजय बघेल हैं। विजय रिश्ते में भूपेश के भतीजे हैं। दो दिन पहले पत्रकारों ने भूपेश से जब यह पूछा कि कक्का-भतीजे में भारी कौन? इस पर उनका जवाब था, रिश्ते में तो हम बाप लगते हैं... यह जवाब इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। दोनों यहां से चौथी बार आमने-सामने हैं।

इससे पहले हुए तीन मुकाबलों में से दो भूपेश और एक विजय जीत चुके हैं। भूपेश पहली बार वर्ष 1993 में इसी सीट से विधायक चुने गए थे। इसके बाद से लगातार यहीं से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इस बार वह यहां से सातवीं बार मैदान में हैं।

पान दुकान पर मिले किसान नरेश पटेल मानते हैं कि भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल अपने कक्का को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उनके अनुसार, सीएम की ओर से की गईं तमाम घोषणाओं पर अमल न होने से यह स्थिति बनी है। यह पूछने पर कि अमित जोगी यहां के चुनाव को कितना प्रभावित करेंगे तो उनका कहना था, क्षेत्र में वह न कभी सक्रिय रहे और न ही उनकी पार्टी का कोई एजेंडा है। ऐसे में वह अधिक से अधिक सतनामी समाज के वोट ही अपने पाले में ला सकेंगे।

पाटन कस्बे के मुख्यमार्ग स्थित चाय की दुकान पर चल रही चुनावी चर्चा में शामिल संजीव वर्मा कांग्रेस की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। यह पूछने पर कि भ्रष्टाचार, घोटालों से घिरी सरकार कितनी चलेगी? उनका कहना था, यह सब भाजपा की देन है। हालांकि, अमित जोगी के जिक्र पर वह थोड़े चिंतित होते हैं। कहा, क्षेत्र में सतनामी समाज का अधिकतर वोट कांग्रेस के पाले में रहता है। अमित यदि एकतरफा वोट बटोर ले गए तो किसका खेल बिगड़ेगा, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते।

जो जैसा धान कूटेगा, वह वैसा चावल पाएगा, कई मामलों में एक से हैं कांग्रेस-भाजपा

अपने तीन कार्यकाल में चाउर वाले बाबा ने इसे आगे बढ़ाया। उनके बाद कका दो कदम आगे निकल गए। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा–कांग्रेस दोनों ने रेवड़ी संस्कृति को और ऊंचाइयां देने का संकल्प दोहरा दिया है। धान के कटोरे में मुद्दों की फसल काटने की होड़ भी कम नहीं है।

नक्सलवाद से जूझते 23 साल के जवान छत्तीसगढ़ को रेवड़ी संस्कृति बुढ़ापे की ओर धकेल रही है। अपने तीन कार्यकाल में चाउर वाले बाबा ने इसे आगे बढ़ाया। उनके बाद कका दो कदम आगे निकल गए। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा-कांग्रेस दोनों ने रेवड़ी संस्कृति को और ऊंचाइयां देने का संकल्प दोहरा दिया है। धान के कटोरे में मुद्दों की फसल काटने की होड़ भी कम नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धान काटते हुए फोटो सामने आने के बाद चुनावी चर्चाओं में यह जुमला आम है...जे जइसन धान काटही, वो वइसन चाउर पाही। मतलब जो जैसा धान कूटेगा, वह वैसा चावल पाएगा।

रेवड़ियों और मुद्दों की खिचड़ी बनाए जाने के बीच हकीकत यह है कि प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए नया हाईवे बनाना तो दूर, पहले से खस्ताहाल राजमार्ग को सुधारने तक का वादा किसी ने नहीं किया। इस मामले में बस्तर और सरगुजा संभाग की हालत सबसे खराब है। दोनों दलों के चुनावी घोषणापत्रों पर मतदाताओं की निराशा साफ नजर आती है। पंडरी बस स्टैंड स्थित चाय की दुकान पर दवा कंपनियों के कुछ प्रतिनिधि कांग्रेस की ओर से कर्जमाफी जारी रखने के साथ जातिगत गणना और केजी से पीजी तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा को भाजपा से अतिरिक्त मान रहे थे।

एक मल्टीनेशनल कंपनी में दवा प्रतिनिधि आरएस पटेल का मानना था, कर्जमाफी से किसानों को राहत मिलती रहेगी। मुफ्त शिक्षा से गरीबों के बचों की पढ़ाई आसान होगी। पर जातिगत गणना से हमें क्या लाभ? सत्तारूढ़ दल ने विकास को मुद्दा ही नहीं समझा। एक अन्य दवा प्रतिनिधि मुनेश शर्मा ने कहा, भाजपा ने राय राजधानी क्षेत्र (एससीआर) बनाने, एम्स जैसेर अस्पताल, तकनीकी शिक्षा संस्थान, निचले तबके के लिए आवास जैसी अछी घोषणाएं की हैं। सड़क नेटवर्क सुधारने या फिर नए हाईवे बनाने की बात बेहतर होती। उन्होंने कहा, बड़े शहरों को छोड़ दें तो कई जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है।

प्रतियोगी छात्र अजीत ठाकुर बोले, हमारी फिक्र तो वोट के लिए दिखाई जाती है। लेकिन, बेरोजगारी दूर करने के वादे पर कोई भी खरा नहीं उतरता। छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग तक में धांधली चल रही है। विकास का मुद्दे छेड़ने पर उन्होंने कहा, कभी हमारे शहर आइए। कहने को नगर निगम है पर चलने को ढंग की सड़क नहीं है। अंबिकापुर की दूरी हमारे यहां से लगभग पौने दो सौ किमी है, लेकिन बस का सफर आठ से नौ घंटे में पूरा होता है।

सड़क संपर्क अछा होने पर ही आएगा निवेश

वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा का कहना है कि रेवड़ियां बांटने में सत्तारूढ़ दल कहीं आगे मिलता है। विकास के मसले पर भाजपा ने कई घोषणाएं की हैं। प्रदेश में निवेश का माहौल बनाने की भी पहल की है। निवेश तो तभी आएगा, जब सड़क संपर्क अछा होगा। चुनावी रेवड़ियां बांटने की होड़ में दोनों दलों ने ध्यान नहीं दिया। पिछले 20 सालों की सरकारों में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा बेहतर रही।

भाजपा के पास नया क्या

प्रदेश में 500 नए जनौषधि केंद्र खोलने की बात कही है। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ की शुरुआत, रायपुर, नया रायपुर, भिलाई और दुर्ग को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के गठन और हर संभाग में आईआईटी की तर्ज पर सीआईटी व एम्स जैसे सिम्स की स्थापना का वादा किया है। जीपीएससी की भर्तियों में पारदर्शिता लाने और पीसीएस भर्ती घोटाले की जांच का एलान किया है।

कांग्रेस के पास नया क्या

लघु और कुटीर उद्योगों के लिए सात सौ नए ग्रामीण औद्योगिक पार्कों का वादा किया है। सभी सरकारी विद्यालयों को स्वामी आत्मानंद स्कूल में तब्दील करने, सरकारी स्कूल-कॉलेजों में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, परिवहन व्यवसायियों और महिला स्वसहायता समूहों के कर्ज माफ करने का वादा किया है। इसके अलावा जातिगत गणना का एलान भी किया है।

दोनों दलों की ये घोषणाएं लगभग समान

भाजपा

- धान का एमएसपी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीद
- भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10 हजार और शादीशुदा महिलाओं को 12 हजार, 500 रुपये में रसोई गैस सिलिंडर
- पीएम आवास योजना में लंबित 18 लाख आवासों का निर्माण पूरा कराएंगे, आयुष्मान भारत योजना में हर परिवार को 5 से 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा
- उद्योगों स्थापना पर 50 फीसदी सब्सिडी के साथ बिना ब्याज के कर्ज

कांग्रेस

- धान का एमएसपी 3,200 रुपये प्रति क्विंटल, प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीद
- भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये, गैस सिलिंडर पर 500 रुपये सब्सिडी
- 17.5 लाख गरीब परिवारों को मिलेंगे आवास, 10 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त।
- युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 50 फीसदी सब्सिडी पर कर्ज

कांग्रेस से बगावत करने वाले इस पूर्व एमएलए को दिखाया बाहर का रास्ता

वर्धा विधानसभा के पूर्व विधायक राजपरिवार के सदस्य योगेश्वर राज सिंह को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया है। उनके ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाते हुए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। योगेश्वर राज सिंह को कांग्रेस के टिकट पर वर्ष 1998 व 2003 में दो बार विधायक चुने गए थे, जिन्होंने भाजपा के डॉ.रमन सिंह को भी हराया था। वर्ष 2008 में हार के बाद उनके सितारे गर्दिश में चले गए, जिसके बाद पार्टी में निष्क्रियता के चलते वापसी नहीं हो सकी। उनके मां व पिता भी कांग्रेसी विधायक रहे। कांग्रेस से कोई तवज्जों न मिलने के चलते वे पार्टी से दूर हो गए। वर्ष 2008 का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के किसी भी गतिविधि में वे शामिल नहीं रहे न ही सक्रियता दिखाई। पांच साल बाद वे सीधे 2013 में विधायक का टिकट मांगने के लिए राजमहल से बाहर निकले। टिकट नहीं मिली, पार्टी ने मोहम्मद अकबर को टिकट दे दिया, जिसके बाद वे फि र राजमहल से बाहर ही नहीं निकले। इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग की, नहीं मिला। निर्दलीय चुनाव लड़ने फ र्म भरा, तो उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के मान मनौव्वल के बाद वे अपना नामांकन वापस ले लिए थे। लेकिन उनकी पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ी। हांलाकि बाद में राहुल गांधी से मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अकबर को अपना समर्थन देने का ऐलान किया था। तभी से जिले में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों खासकर मोहम्मद अकबर से राजपरिवार के संबंध बिगड़ते चले गए।

6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित

दरअसल हाल ही के चुनाव में उनके चचेरे भाई खड़गराज सिंह आम आदमी पार्टी से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं जिनके प्रचार के लिए योगेश्वर राज सिंह गए थे। इसी के चलते पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। हांलाकि ये तो सिर्फ एक बहाना माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को अवसर मिल गया, नहीं तो वैसे भी योगेश्वर राज सिंह की कोई पूछ परख नहीं हो रही थी। योगेश्वर राज सिंह को पांच साल कांग्रेस ने कभी याद नहीं किया। हाल ही में जब चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी कवर्धा आए थे, तो पार्टी ने उन्हें बुलाया नहीं था। पूछ परख ना होने के चलते उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नाराजगी भरा लेटर भी लिखा। लोगों में उसी समय चर्चा थी कि वे पार्टी से इस्तीफा देकर ससम्मान दूर हो जाते तो शायद अच्छा था। लेकिन वे पार्टी से इस्तीफ ा नहीं दिए, जैसे ही 7 नवंबर को मतदान हुआ, देर रात तक पार्टी ने उनके निष्कासन का लेटर जारी कर दिया।

चुनावी हलचल...चुनाव प्रचार के बीच जमकर चल रही रस्साकसी

टिकट की ख्वाइश पूरी न होने और विधायक बनने का सपना लंबा होता देख कुछ दावेदारों ने अपनी चाल बदल ली है। अंदर ही अंदर भितरघात तो शुरू हो ही चुका है वहीं बुधवार को दूसरा रुझान एक ऑडियो के रूप में आया है। जिसमें करोड़ों में टिकट बिकने की चर्चा की जा रही है। इस बात के सामने आने के बाद पूरे दिन गहमा गहमी की स्थिति रही। इस ऑडियो में जिस व्यक्ति की आवाज है और जो बड़े नेता पर करोड़ों के लेनदेन का आरोप लगा रहा है वो तो पूरे दिन जैसे राम-राम करता हुआ शरणागत बनकर सफाई देता रहा। बहरहाल तखतपुर, कोटा व बेलतरा इन तीनों सीटों पर दोनों ही दलों में कुछ न कुछ, कहीं न कहीं असंतोष दिख रहा है। आलम यह है कि प्रचार-प्रसार में तो सब साथ नजर आ रहे हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है, ये बात स्वयं प्रत्याशी भी समझ रहे हैं, इसीलिए मन ही मन सशंकित हैं। इसपर भी दूसरा तुर्रा बुधवार को सामने आया जब एक कथित ऑडियो एक असंतुष्ट की ओर से वायरल किया गया है। ऑडियो में क्या सच्चाई है ये तो जांच के बाद स्पष्ट होगा फिलहाल इस बात की चर्चा लोगों की जुबान पर है, लोग रुचि भी ले रहे हैं। कोटा सीट की बात करें तो यहां एक दल के प्रत्याशी ने चीजों को अपने स्तर पर काफी नियंत्रित किया है पर ये भी सच है कि थोड़ी बहुत लीकेज बनी हुई है। कोटा से बड़ी संख्या में कांग्रेसी टिकट की आस पाले हुए थे। जब सूची जारी हुई तो पर्यटन मंडल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाया गया। इससे बहुतों के मंसूबों पर पानी फिर गया। इधर भाजपा में स्थानीय नेता टिकट की आस में थे, लेकिन भाजपा ने भी जशपुर राजघराने के प्रबल प्रताप सिंह जूदेव को टिकट दिया। बतादें कि यहां सूची जारी होने से पहले ही जब जूदेव का नाम लीकआउट हुआ था, तभी से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। अब उसका असर सतह पर दिख रहा है। कोटा सीट की बात करें तो यहां एक दल के प्रत्याशी ने चीजों को अपने स्तर पर काफी नियंत्रित किया है पर ये भी सच है कि थोड़ी बहुत लीकेज बनी हुई है। कोटा से बड़ी संख्या में कांग्रेसी टिकट की आस पाले हुए थे। जब सूची जारी हुई तो पर्यटन मंडल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाया गया। इससे बहुतों के मंसूबों पर पानी फिर गया। इधर भाजपा में स्थानीय नेता टिकट की आस में थे, लेकिन भाजपा ने भी जशपुर राजघराने के प्रबल प्रताप सिंह जूदेव को टिकट दिया। बतादें कि यहां सूची जारी होने से पहले ही जब जूदेव का नाम लीकआउट हुआ था, तभी से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। अब उसका असर सतह पर दिख रहा है। कुछ माह पहले शहर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सभा हुई थी। इस सभा में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी थी उसे देखकर यह माना जा रहा था कि तीसरा विकल्प तैयार हो रहा है लेकिन उस सभा की भीड़ और वर्तमान स्थिति में काफी फर्क आ गया है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

भाजपा ने तेलंगाना के लिए 14 उम्मीदवारों की सूची जारी की

हैदराबाद। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की अपनी अंतिम सूची जारी की। उम्मीदवारों में पूर्व एमएलसी वरिष्ठ नेता एन रामचंदर राव शामिल हैं, जिन्हें यहां मल्काजगिरी से मैदान में उतारा गया है। सूची में अन्य उम्मीदवार हैं - ए श्रीदेवी (बेलमपल्ली-एससी), दुग्याला प्रदीप (पेद्दापल्ली), देशपांडे राजेश्वर राव (संगारेड्डी), येनुगु सुदर्शन रेड्डी (मेडचल), रवि कुमार यादव (सेरिलिंगमपल्ली), राहुल चंद्रा (नामपल्ली), के. महेंद्र (चंद्रयानगुट्टा), श्री गणेश नारायण (सिकंदराबाद छावनी-एससी), कोंडा प्रशांत रेड्डी (देवरकद्रा), अनुगना रेड्डी (वानापर्थी), राजगोपाल (आलमपुर-एससी), के पुल्ला राव (नरसंपेट) और पेरुमरपल्ली विजया राजू (मधिरा-एससी)। बीजेपी सूत्रों ने यह भी कहा कि अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की एनडीए सहयोगी जनसेना विधानसभा चुनाव में कुल 119 सीटों में से आठ पर चुनाव लड़ेगी। 2 नवंबर को, भगवा पार्टी ने आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए 35 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की।

भाजपा के पास बोलने का कोई मुद्दा ही नहीं : गहलोत

जयपुर। राजस्थान में चुनावी शोर लगातार जारी है। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो चुका है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरूवार को उदयपुर में भाजपा के लिए प्रचार किया था। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा था। अब उनपर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वे घबरा गए हैं। गहलोत ने कहा कि भाजपा के पास हमारे (कांग्रेस) खिलाफ बोलने का कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वह बिना मुद्दों के मुद्दा बना रही है। वे (भाजपा) समझ गए हैं कि हमारी दाल गल नहीं रही है, हम इन्हें (कांग्रेस) जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पहलें हमने 10 गारंटियां दीं। अब हमने 7 गारंटियों की बात की है तो वह और घबरा गए हैं।

केजरीवाल को फंसाने की हो रही साजिश: संजय सिंह

नईदिल्ली। आप नेता संजय सिंह, जिन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संबंध में गिरफ्तार किया गया है, ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाने की एक बड़ी साजिश चल रही है। मामले के सिलसिले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए गए सिंह ने कहा कि सिर्फ एक साजिश नहीं, केजरीवाल के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। अदालत परिसर में कई पुलिसकर्मियों के साथ मौजूद सिंह ने परोक्ष रूप से केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, केजरीवाल को फंसाने की एक बड़ी साजिश है। सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, वे केजरीवाल के साथ कुछ और भी बुरा करने जा रहे हैं। वे कुछ बड़ा अंजाम देंगे।इस बीच दिल्ली की अदालत ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 24 नवंबर तक बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिंह को तीन पत्रों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जो एक संसद सदस्य के रूप में विकास कार्यों के संबंध में दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को संबोधित थे।

सुखबीर बादल का भगवंत मान पर सीधा हमला

बठिंडा। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया है कि वो कानून-व्यवस्था में पूरी तरह से फेल है। सूत्रों के मुताबिक सुखबीर बादल ने बठिंडा में हुए आपराधिक घटना के एक सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए आप सरकार पर तीखा हमला बोला है। सीसीटीवी में दिखाया गया है कि एक अपराधी कथित तौर पर एक महिला की चेन छीनने की कोशिश करता है और उसके लिए महिला की गर्दन पकड़ लेता है। अकाली नेता बादल ने सीएम मान को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का कठपुतली करार दिया है। उन्होंने एक्स के पोस्ट कहा, स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की मांग है लेकिन कठपुतली सीएम अपने दिल्ली बॉस अरविंद केजरीवाल के ड्राइवर की भूमिका निभाने में व्यस्त हैं।

एथिक्स कमेटी किसी कंगारू कोर्ट से कम नहीं:महुआ मोइत्रा

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस की फायरब्रांड नेता और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने कैश फॉर क्वेरी मामले में अब सीधे तौर पर संसद की एथिक्स कमेटी पर हमला किया है। सांसद मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि मामले की जांच करने वाली लोकसभा की एथिक्स कमेटी किसी कंगारू कोर्ट से कम नहीं है। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किये एक पोस्ट में महुआ मोइत्रा ने कहा कि संसद की एथिक्स कमेटी के पास इस तरह के अधिकार नहीं हैं कि वो उन्हें लोकसभा से निष्कासित करने का फैसला सुनाएं। सांसद मोइत्रा ने एक्स पर लिखा, संसदीय इतिहास में एथिक्स कॉम द्वारा अनैतिक रूप से निष्कासित होने वाली पहले व्यक्ति के तौर पर गर्व है, जिसके जनादेश में निष्कासन शामिल नहीं है। पहले निष्कासन और फिर सरकार से सबूत खोजने के लिए सीबीआई से कहने के लिए कहें। कंगारू कोर्ट, शुरू से अंत तक बंदरबांट है।

बिहार के सीएम के राजनीतिक जीवन का चल रहा क्लाइमेक्स?

नीतीश कुमार-मांझी आमने-सामने

नईदिल्ली। बिहार की राजनीति में इस वक्त काफी हलचल दिखाई दे रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में हैं। सेक्स एजुकेशन पर ज्ञान देने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को खरीखरी सुनाई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 09 नवंबर को सरकार के जाति-आधारित सर्वेक्षण पर संदेह करने के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के संस्थापक जीतन राम मांझी को आड़े हाथों लिया। नीतीश कुमार को जवाब देते हुए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी और बिहार के पूर्व सीएम ने कहा है चल रहे विधानसभा सत्र में अपनी टिप्पणी पर नीतीश कुमार की आलोचना की, जिसमें बाद वाले ने अपना आपा खो दिया और कहा कि उनकी मूर्खता ने उनके पूर्व शिष्य मांझी को राज्य में सत्ता की सर्वोच्च सीट पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया।बिहार विधानसभा में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पूर्व सहयोगी जीतन राम मांझी पर जमकर बरसे और कहा कि उनकी ''मूर्खता'' के कारण वह राज्य में सत्ता की सर्वोच्च सीट पर आसीन हुए। विपक्षी पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख मांझी द्वारा सदन में राज्य सरकार के जाति सर्वेक्षण पर संदेह व्यक्त करने पर नीतीश कुमार अपनी सीट से खड़े हुए और मांझी की ओर इशारा करते कहा, ''ये बोलता है कि हम मुख्यमंत्री थे। मेरी मूर्खता की वजह से यह मुख्यमंत्री बने। इसे कोई समझ है?'' नीतीश के इस कथन के बाद भाजपा सदस्य आपत्ति जताते हुए हंगामा करने लगे।

बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश से उनके सहयोगी मंत्रियों को शांत होने और अपनी सीट ग्रहण करने का आग्रह करते हुए देखा गया पर सत्तर वर्षीय जदयू नेता तब तक शांत नहीं हुए जब तक कि उन्होंने मांझी के खिलाफ जमकर भड़ास नहीं निकाल ली। उन्होंने मीडिया गैलरी की ओर ऊपर की ओर नजर घुमाते हुए यह भी कहा, ''पत्रकारों को भी पूरे तथ्य पता होने चाहिए। वे इस आदमी को खूब प्रचारित करते रहते हैं।'' विरोध में खड़े हुए भाजपा सदस्यों से नीतीश ने कहा, ''यह आदमी हमेशा से आपके साथ रहना चाहते थे। जब एक साल पहले मैंने आपको (राजग) छोड़ा था तो मैंने उनसे यहीं रहने के

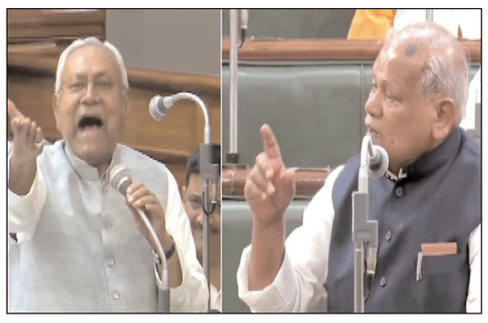

लिए कहा था, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वह मेरे साथ आना चाहते हैं। अब वह भाग गये हैं। वह गवर्नर बनना चाहते हैं। कृपया उन्हें उपकृत करें।''

मुख्यमंत्री तब अपनी सीट पर बैठे जब विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने उनसे विनती करते हुए कहा, '' वह आपके आशीर्वाद के कारण ही मुख्यमंत्री बने थे।'' मांझी के पक्ष में भाजपा सदस्यों के हंगामे के बीच बिहार विधानसभा की कार्यसूची में शामिल कार्य खत्म होने के तुरंत बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी।आज की कार्यवाहियों मेंसर्वसम्मति से पारित वे विधेयक भी शामिल हैं जिनमें एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी के लिए कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया है। बाद में सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में नाराज मांझी ने कहा, ''मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री से शिकायत करूंगा। मैं उन्हें बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करूंगा। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने महिलाओं के बारे में अपनी टिप्पणी से राज्य को शर्मसार किया। उनके बार-बार इस तरह के रवैये से पता चलता है कि अब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें इतना महत्वपूर्ण पद नहीं सौंपा जा सकता है।''

मांझी के पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनके दोनों ओर भाजपा के विधायक भी खड़े थे, जिन्होंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख के साथ एकजुटता व्यक्त की और नीतीश पर 'एक दलित का अपमान करने' का आरोप लगाया। मांझी मई, 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री उस समय बने थे, जब नीतीश ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी

नीतीश के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा का प्रदर्शन

पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ धरना दिया और उनके इस्तीफे की मांग की। पटना में राज्य विधानसभा में नीतीश कुमार के अपमानजनक बयान को लेकर एनडीए विधायकों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच, बिहार विधानसभा में जातिगत आरक्षण को 65 प्रतिशत तक बढ़ाने का विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेताओं ने एनडीए विधायकों को लड्डू खिलाए। लेकिन, एनडीए विधायकों ने पटना में विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर मिठाइयां फेंकीं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। राजद के लोग गुंडा राज स्थापित करते हैं... वे (तेजस्वी प्रताप) भूल गए कि उनके पिता ने बिहार में जंगल राज स्थापित किया था।

जदयू की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। हालाँकि, एक साल से भी कम समय में जदयू में विभाजन की कोशिश करने के आरोपों का सामना कर रहे मांझी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पडा था जिसके बाद नीतीश की मुख्यमंत्री के रूप में वापसी हुई। मांझी ने बाद में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नामक अपना एक दल बनाया और राजग के सदस्य के रूप में 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ा। नीतीश की 2017 में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग में वापसी के कुछ महीने बाद, मांझी महागठबंधन में शामिल हो गए जो तब केवल राजद और कांग्रेस के साथ रह गया था। मांझी 2020 में फिर से राजग में लौट आए और उनकी पार्टी को जदयू के कोटे से चुनाव लड़ने के लिए सीटें दी गईं तथा उनके बेटे संतोष सुमन को मंत्री पद मिला। पिछले साल जब नीतीश ने राजग छोड बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बना ली तो मांझी भी उनके साथ ही रहे जिससे उनके बेटे को अपना मंत्री पद बरकरार रखने में मदद मिली।

मध्यप्रदेश में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का मोदी पर प्रहार

जीएसटी छोटे व्यापारियों को खत्म करने हथियार: राहुल

भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए शुक्रवार को राहुल गांधी पहुंचे। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी ने छोटे-मध्यम व्यवसाइयों और व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया जिससे देश में भारी बेरोजगारी पैदा हुई। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कर्ज के कारण 18 साल में करीब 18,000 किसानों ने आत्महत्या की। राहुल ने कहा कि भाजपा की सरकार आई और उन्होंने छोटे व्यापारियों पर आक्रमण शुरू कर दिया। जीएसटी टैक्स नहीं है बल्कि ये छोटे व्यापारियों, किसानों के खिलाफ हथियार है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है... भाजपा सरकार आपसे यानी गरीबों से जीएसटी लेती है और पूरा का पूरा पैसा 3-4 उद्योगपतियों को पकड़ा देती है।

राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं युवाओं से पूछता था कि आपने क्या पढ़ाई की है और क्या कर रहे हो? वे कहते थे- इंजीनियरिंग की है, मेडिकल किया है, लीगल स्ट्डीज की है, लेकिन बेरोजगार हैं। जहां भी भाजपा की सरकार है, वहां युवा बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर मुझे एक युवा कुली मिला। मैंने उससे पूछा कि कुली बनने से पहले तुम्हारा सपना क्या था? उसने कहा- मैं इंजीनियर बनना चाहता, सिविल इंजीनियरिंग की है, डिग्री ली है, हजारों रुपए खर्च किए हैं। लेकिन मुझे रोजगार नहीं मिला, इसलिए कुली का काम कर रहा हूं। यह इस देश की सच्चाई है। उन्होंने कहा कि रोजगार बड़े उद्योगपति नहीं देते, रोजगार छोटे व्यापारी देते हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले हिन्दुस्तान में लाखों छोटे-छोटे यूनिट हुआ करते थे, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलता था। नरेंद्र मोदी जी ने छोटे व्यापारियों पर नोटबंदी और जीएसटी लगाकर आक्रमण करना शुरु कर दिया। जीएसटी टैक्स नहीं है, यह छोटे व्यापारियों को खत्म करने का हथियार

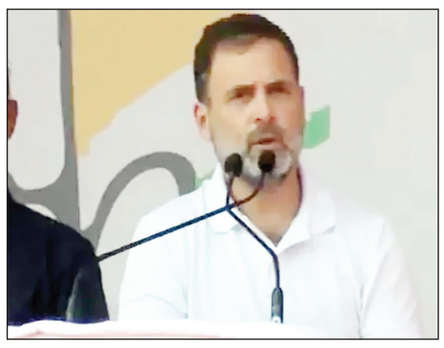

है। उन्होंने कहा कि देश के दलित, आदिवासी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब लोग जीएसटी देते हैं। मोदी सरकार गरीबों से जीएसटी लेकर बैंक का पूरा पैसा 3-4 उद्योगपतियों को सौंप देती है। सतना में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, मैंने पीएम मोदी का भाषण सुना, वह हर भाषण में हर जगह कहते थे कि मैं ओबीसी समुदाय से हूं, वह बार-बार यह कहकर प्रधानमंत्री बन गए। वह एक दिन में कम से कम 1 सूट पहनते हैं लाखों रुपये की कीमत। क्या आपने मोदी जी को अपने कपड़े दोहराते हुए देखा है? मैं यह एक ही सफेद शर्ट पहनता हूं। क्या आप जानते हैं कि जैसे ही मैंने जाति आधारित जनगणना के बारे में बोलना शुरू किया, उनके भाषणों से जाति क्यों गायब हो गई। जब से मैंने इसके बारे में बोलना शुरू किया, मोदी ने शुरू कर दिया यह कहते हुए कि भारत में कोई जाति नहीं है।

राहुल गांधी ने कहा बड़े उद्योगपतियों, अरबपतियों, पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह ने मिलकर हमारे सरकार चुरायी क्योंकि वह जानते थे कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार अदाणी के लिए काम नहीं करेगी बल्कि किसानों, मजदूरों और छोटे दुकानदारों के लिए काम करेगी।

खेल
प्रमुख समाचार

क्या सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड दोहराएगा 2019 का इतिहास ?

नईदिल्ली। आईसीसी विश्व कप 2023 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 15 नवंबर को पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है। प्वाइंट टेबल में अभी जो टीम टॉप चार में शामिल है उन पर गौर करें तो यह कहा जा सकता है कि भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होगा।

न्यूजीलैंड अभी प्वाइंट टेबल में चौथे स्थान पर है और उसने अपने सभी लीग मैच खेल लिए हैं। न्यूजीलैंड के कुल अंक 10 हैं उसने पांच मैच जीते हैं और चार हार हैं। रन रेट +0.743 है। जबकि भारत शीर्ष पर बना हुआ है। भारत ने आठ मैच में आठों जीते हैं और कुल अंक 16 अर्जित किया है। विश्व कप के नियमों के अनुसार अभी प्वाइंट टेबल की जो स्थिति है एक नंबर और चार नंबर की टीम के बीच 15 नवंबर को सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है। इस लिहाज से भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला होना तय है।

पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ 11 नवंबर को मैच है, लेकिन उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड पर बड़ी जीत दर्ज करनी है होगी तभी वह सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, जो आसान नहीं है। इस परिस्थिति में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला लगभग तय है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि न्यूजीलैंड ही वो टीम है, जिसने 2019 के विश्व कप में भारत का खेल खराब किया था।

विश्व कप 2019 में न्यूजीलैंड ने भारत को मैनचेस्टर के ग्राउंड पर 18 रन से हरा दिया था, जिससे भारत का विश्वकप के फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया था। इस मैच में एमएस धोनी और रविंद्र जडेजा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन धोनी के आउट होते ही सारी उम्मीदें भी ध्वस्त हो गई थी। धोनी जब आउट हुए थे उस वक्त टीम को 10 गेंद पर 25 रन चाहिए थे, लेकिन धोनी रनआउट हो गए।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 72 अंक मजबूत निफ्टी 19,400 के पार

नईदिल्ली। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार दिन के ज्यादातर समय नुकसान में रहा। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 72.48 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 30 अंक की बढ़त दर्ज की गई। व्यापक बाजारों में, बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में क्रमश: 0.33 प्रतिशत और 0.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 72.48 अंक यानी 0.11 फीसदी की बढ़त के साथ 64,904.68 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 65,014.06 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 64,580.95 तक आया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 30.05 अंक यानी 0.15 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 19,425.35 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 19,451.30 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 19,329.45 तक आया।

हिंडाल्को का नेट प्रॉफिट 2,196 करोड़ रुपये पर स्थिर

नईदिल्ली। आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 2,196 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का पिछले वर्ष समान तिमाही में शुद्ध लाभ 2,205 करोड़ रुपये रहा था। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने बीएसई को दी जानकारी में बताया कि जुलाई-सितंबर अवधि में कंपनी की एकीकृत कुल आय घटकर 54,632 करोड़ रुपये हो गई। पिछले साल दूसरी तिमाही में यह 56,504 करोड़ रुपये थी। हिंडाल्को राजस्व के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी एल्युमीनियम कंपनी है।

अक्टूबर में यात्री वाहनों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर

नईदिल्ली। त्योहारी सीजन की मजबूत मांग के दम पर अक्टूबर में यात्री वाहनों की थोक बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अक्टूबर में खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़कर 3,89,714 इकाई रही। अक्टूबर 2022 में यह 3,36,330 इकाई थी। इसी तरह तिपहिया खंड में भी अक्टूबर में अभी तक की सबसे अधिक 76,940 इकाइयों की मासिक आपूर्ति की गई। यह संख्या पिछले साल से 42 प्रतिशत अधिक है, जब 54,154 इकाइयों की आपूर्ति की गई थी। वाहन बनाने वाली कंपनियों के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने कहा, '' यात्री वाहनों तथा तिपहिया वाहनों दोनों ने अक्टूबर में अभी तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की है। दोपहिया वाहन खंड ने भी अक्टूबर 2023 के महीने में अच्छी बिक्री दर्ज की।''

दिवाली से पहले धनतेरस पर सोने की बिक्री में तेजी

नईदिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े सोने के उपभोक्ता देश भारत में दिवाली से पहले धनतेरस पर सोने तथा चांदी की खरीदारी शुक्रवार को सोने की कीमतों में नरमी के साथ उपभोक्ता मांग में सुधार के चलते सकारात्मक रही। सोने का भाव 28 अक्टूबर को 63,000 रुपये के उच्चतम स्तर से 800-1,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (24 कैरेट) तक गिर गया। इससे धनतेरस पर खरीदारी को बढ़ावा मिला जिसे हिंदू पंचांग में कीमती धातुओं से लेकर अन्य वस्तुओं की खरीद के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। कारोबारियों को उम्मीद है कि सोने की बिक्री पिछले साल के स्तर को पार कर जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार को सोने की कीमतें 400 रुपये गिरकर 60,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। दिल्ली में 2022 में धनतेरस के दिन सोने की कीमतें करों को छोड़कर 50,139 रुपये प्रति 10 ग्राम थीं।

देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी चुनौती है जहरीली हवा

अनिल तिवारी

वर्तमान त्योहारी सीजन के दौरान आर्थिक रंगत धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ ही रही थी कि जहरीली हवा ने लंगड़ी मार दी। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण से भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में साल दर साल लगभग 0.56 प्रतिशत की कमी आ रही है, क्योंकि जीडीपी की गणना में शामिल वस्तुओं एवं सेवाओं पर वायु प्रदूषण नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। आज भारत में वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित स्तर का लगभग 20 गुना और भारत के अपने मानकों से दो गुने से भी अधिक है।

कोरोना महामारी के बाद से ही दुनिया के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है, लेकिन भारत की स्थिति चमकते सितारे की तरह है। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2047 तक यानी कि भारत की आजादी के जब 100 साल पूरे होंगे, भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में यह 3.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2030 तक भारत जापान और जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।

ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच के ताजा अध्ययन से भी इसकी पुष्टि हुई है। फिच ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर टॉप-10 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा रहने वाली है। रेटिंग एजेंसी ने विकास दर अनुमान को भी 0.7% बढ़ाकर अब 6.2 प्रतिशत कर दिया है और कहा है कि वर्ष 2023-24 के लिए भारत की विकास दर 6.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। एस एंड पी का भी अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत 7.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया

की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। लेकिन वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के साथ-साथ अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। प्रदूषण के लगातार गहराते संकट को देखते हुए अब तो यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि वायु प्रदूषण से होने वाला आर्थिक नुकसान 2024 तक भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के सपने पर भी पानी फेर सकता है।

प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण माना जाता है। यह दुनिया में असमय मृत्यु का चौथा सबसे बड़ा कारण है। इसके कारण सर्दियां आते ही स्मॉग की काली छाया उत्तर भारत के अधिकांश शहरों को अपने दामन में समेट लेती हैं। प्रदूषण का सबसे प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्य और उत्पादकता पर पड़ता है। दुनिया में कोई भी कार्य मानव संसाधन की बदौलत ही किया जाता है। लेकिन जल, वायु, भूमि और ध्वनि प्रदूषण शरीर को रुग्ण कर देता है, जिससे स्वास्थ्य के मद की लागत बढ़ जाती है और उत्पादकता कम हो जाती है।

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के अनुसार विकासशील देशों में वायु प्रदूषण के कारण लोग अपने स्वास्थ्य पर अपने कुल खर्च का सात प्रतिशत व्यय करते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर और ग्रीन पीस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था को सालाना 15 हजार करोड़ डालर यानी 1.05 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। यदि सकल घरेलू उत्पाद के रूप में देखें तो यह नुकसान कुल जीडीपी के 5.4त्न के बराबर होता है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि प्रदूषण के कारण हर साल न सिर्फ लाखों की संख्या में मौतें हो रही हैं बल्कि अर्थव्यवस्था को देश की जीडीपी का 7% यानी लगभग 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भी हो रहा है। यह रकम वित्तीय घाटे के कमोबेश दोगुनी बैठती है। गौर करने की बात है कि दुनिया में विकसित देश जब पर्यावरण से समझौता करते हैं तो यही कहते हैं कि हमें अर्थव्यवस्था को पहले देखना है, बाकी बाद में। अब जब अपने देश में वायु प्रदूषण से देश को हर साल 14 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का आंकड़ा निकल कर आ रहा है तो क्या इसका एक मतलब यह नहीं है कि प्रदूषण से जान माल का दोहरा नुकसान हो रहा है?

ना पूछो कहाँ पहुँचे,कहाँ ठहरे, हुआ क्या-क्या...

छत्तीसगढ़,राजस्थान की कांग्रेस सरकार हो,मप्र की भाजपा सरकार हो या तेलंगाना की गैर कॉंग्रेस, गैर भाजपा सरकार हो,सभी पर भारी भरकम कर्ज है और अभी 2023 के चुनावी वादों में जमकर रेवड़ी बांटी जा रही है, सवाल उठ रहा है इन प्रदेशों में वित्तीय प्रबंधन कैसे हो सकेगा!आय बढ़ाने के संसाधन जुटाना मज़बूरी ही होगा।अगर सिर्फ मध्य प्रदेश,राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बात करें तो वर्ष 2019 से वर्ष 2022 के दौरान राज्य की सरकारों ने कुल 5,03,126 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है।रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में मप्र,राजस्थान और छग को लेकर साफ तौर पर कहा है कि इन पर बढ़ता कर्ज लंबे समय तक बरकरार नहीं रखा जा सकता है।वैसे इन राज्यों की आगामी सरकारों के पक्ष में अच्छी बात यह है कि कोविड के बाद भारतीय इकोनॉमी जिस तेजी से पटरी पर लौटी है उसका असर इन राज्यों के राजस्व पर भी दिखने के आसार हैं।ऐसे में अगर नई सरकारों की तरफ से कुशल वित्त प्रबंधन दिखाया जाए तो कर्ज लौटाने की चुनौती भी पार की जा सकती है।रिजर्व बैंक की तरफ से राज्यों के बजट पर हर वर्ष एक अध्ययन रिपोर्ट जारी होती है,जिसे राज्यों की वित्तीय स्थिति और इनके सरकार के आर्थिक प्रबंधन की स्थिति जानने की सबसे सटीक रिपोर्ट माना जाता है। चुनाव में जाने वाले चार प्रमुख राज्यों की मौजूदा सरकारों ने अपने कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में जमकर कर्ज लिया है।मप्र ने 89,444 करोड़ राजस्थान सरकार ने 147,600 करोड़,छग ने 28,680 करोड़ रुपये और तेलंगाना सरकार ने 2,37,402 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है।मार्च 2023 तक मध्य प्रदेश पर कुल 3,78,617 करोड़ रुपये, राजस्थान पर 5,37,013 करोड़ रुपये,तेलंगाना पर 3,66,606 करोड़ रुपये का कुल कर्ज है।छग की सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया था कि जनवरी 2023 तक उस पर कुल 82,125 करोड़ रुपये कर्ज है।कर्ज की राशि में भारी वृद्धि की अहम वजह कोरोना महामारी का काल था जिसकी वजह से देश के तकरीबन सभी राज्यों के राजस्व के अपने स्त्रोत सूख गये।उल्लेखनीय तथ्य यह है कि दिसंबर, 2023 में इन राज्यों में जिसकी भी सरकार बनेगी उसे आने वाले पांच वर्षों के दौरान उक्त कर्ज के एक बड़े हिस्से की अदाएगी करनी होगी। आरबीआई का ही डाटा बताता है कि वर्ष 2024-25 से वर्ष 2028-29 के दौरान मप्र को बकाये कुल कर्ज 40.3लराजस्थान की सरकार को 40.5ल तेलगांना की सरकार को 29.7ल कर्ज की राशि चुकानी होगी। छग की नई सरकार को मौजूदा कर्ज की राशि का तकरीबन 70.4 ल चुकाना होगा।

कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के 3 प्रत्याशी...?

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का मानना है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी के उम्मीदवार भाजपा के तीन उम्मीदवारों ईडी,सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग से चुनाव लड़ रहे हैं।खरगे ने छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा के दिमाग में है कि उसने हिंदुओं का ठेका लेकर रखा हुआ है, लेकिन क्या हम हिंदू नहीं हैं,मेरा नाम मल्लिकार्जुन है जिसका मतलब शिव होता है।

11 वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं डॉ चरणदास महंत

छग सहित देश की राजनीति में डा चरणदास महंत का बड़ा नाम है। नायब तहसीलदार की प्रशासनिक नौकरी छोड़कर विधायक,मप्र में मंत्री,केंद्र में डॉ. मनमोहन सिंह सरकार में राज्य मंत्री,छग में विधानसभाअध्यक्ष,प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व भी

सम्हाल चुके महंत इस बार 11 वां चुनाव (पत्नी ज्योत्सना महंत का लोस चुनाव शामिल कर लें तो 12)लड़ रहे हैं।छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर डॉ चरणदास महंत वर्ष 1980 में पहली बार मध्यप्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए।इसके बाद वर्ष 1985, 1993 और 2018 में भी विधायक बने।इसके पहले तीन बार लोकसभा के लिए चुने गए।वर्ष 1998,1999 और 2009 के लोकसभा चुनाव में वह क्रमशः बारहवीं, तेरहवीं और पंद्रहवीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।कांग्रेसी बिसाहू दास महंत के परिवार में जन्मे चरणदास महंत ने एमएससी,एमए, एलएलबी,पीएचडी की डिग्री ली है(छग में सर्वाधिक पढ़े लिखे राजनेता..)।उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत अभी लोकसभा की सांसद हैं।

राजधानी,आसपास औरब्राह्मण उम्मीदवार....?

छग की राजधानी रायपुर तथा आसपास काफ़ी सालों बाद कांग्रेस और भाजपा ने ब्राह्मण उम्मीदवारों को मौका दिया है।रायपुर उत्तर विधानसभा से भाजपा के पुरँदर मिश्रा को चुनाव समर में उतरा है उनका मुकाबला सरदार कुलदीप जुनेजा से है तो भाजपा ने भिलाई से प्रेम प्रकाश पांडे,धरसींवा से अनुज शर्मा,भाटापारा से शिवरतन शर्मा को टिकट दिया है तो कॉंग्रेस ने रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास (त्रिवेदी) रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय,रायपुर ग्रामीण से पंकज सत्यनारायण शर्मा तथा राजिम विस से अमितेश शुक्ला, बलौदाबाजार से शैलेश नितिन त्रिवेदी को टिकट दिया है। अन्य जाति के लोग तो ऐसे में सक्रिय हो जाते....?खैर देखना है कि कितने ब्राह्मण विधानसभा जीतकर पहुंचते हैं?वैसे शारदा चरण तिवारी, तरुण प्रसाद चटर्जी आदि भी रायपुर से विधायक बनते रहे हैं। कॉंग्रेस के बड़े नेता राजेंद्र तिवारी को भी विद्या भैया ने रायपुर से प्रत्याशी बनाया था पर तरुण चटर्जी ने 1993 में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र तिवारी को 21586 वोट के भारी अंतर से हराया। उसके बाद से राजेंद्र तिवारी ने कभी टिकट ही नहीं मांगी..?

और अब बस.....

- रायपुर से लगातार विधायक बन रहे भाई बृजमोहन अग्रवाल पर हमला दुर्भाग्यजनक ही कहा जा सकता है।
- छग के सीएम पर महादेव ऐप को लेकर लगाया गया आरोप लगता है टांय टांय फिस्स हो गया...?
- भाजपा के 3 महामंत्री ओपी चौधरी,केदार कश्यप और विजय शर्मा के चुनाव परिणाम पर सभी की नजर लगी है?
- भाजपा के पक्ष में ब्राम्हणों तथा उच्च वर्ग को एकजुट करने पूर्व आईएएस गणेशशंकर मिश्रा लगे हुये हैं।

बृजमोहन ने महामाया मंदिर वार्ड में जनसंपर्क यात्रा कर मांगा जीत का आशीर्वाद

रायपुर। गुरुवार को अपने ऊपर हुए हमले के बाद छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शुक्रवार को एक बार फिर जनता के बीच में पहुंचे। बृजमोहन अग्रवाल ने महामाया मंदिर वार्ड में जनसंपर्क यात्रा निकाली और जीत का आशीर्वाद मांगा। आज की यात्रा का शुभारंभ बूढ़ेश्वर मंदिर चौक से हुआ। इसके बाद शीतला मंदिर, ब्रह्मपुरी बिरंचि मंदिर रोड, राज टावर, गांधी मैदान, गौरा चौरा, दत्तात्रेय मंदिर गली, महामाया पारा गली, गजराज चौक, योगेश गली, गोवर्धन चौक, पटेल पारा, गजराज चौक, ढीमर पारा, पटेल विद्या मंदिर, सीएसईबी सब स्टेशन, चंदन किराना स्टोर्स, सावरा गली, हिम्मत अली गली, मेन रोड लक्ष्मी नारायण स्कूल, बजरंगबली मंदिर, देवकी बाल उद्यान होते हुए सती मंदिर पहुंची जहां आज यात्रा का समापन हुआ। आज के अभियान के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, अगर भूपेश बघेल की सरकार में पूर्व मंत्री और 7 बार के विधायक पर हमला हो सकता है। तो जनता कितनी सुरक्षित है। इसको समझा जा सकता है। उन्होंने भाजपा की सरकार बनने पर योगी आदित्य नाथ की तरह छत्तीसगढ़ में गुंडों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की बात कही। इसके साथ ही बृजमोहन ने बदहाल सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा को बड़ी समस्या बताया हैं। उन्होंने सरकार बनने के बाद जनता को इन मूलभूत समस्याओं से छुटकारा दिलाने का आश्वासन दिया।

बदसलूकी पर संतों ने की निंदा

रायपुर। रायपुर में गुरुवार को विधायक बृजमोहन अग्रवाल के साथ धक्का-मुक्की की गई। भीड़ के उपद्रव के बीच बृजमोहन पर हमले का प्रयास किया गया। इस घटना की शदाणी दरबार के संत युधिष्ठिर लाल ने निंदा की है। शुक्रवार को संत बृजमोहन अग्रवाल से मिलने उनके घर पहुंचे। शदाणी दरबार तीर्थ के प्रमुख संत युधिष्ठिर लाल ने घटना को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना शहर के शांत वातावरण को बिगाड़ती हैं, लेकिन जीत सत्य की होगी। बृजमोहन के परिजनों ने भी संत का आर्शीवाद लिया। बता दें कि 9 नवंबर को हुए कांड में पुलिस ने बैजनाथ पारा में रहने वाले चिंटू नाम के युवक पर केस दर्ज किया है। चुनाव प्रचार के दौरान कुछ युवकों ने बृजमोहन के साथ बदसलूकी की थी। बृजमोहन ने दैनिक भास्कर को बताया था कि एजाज ढेबर और अनवर ढेबर के लोगों ने उनकी हत्या करने की कोशिश की थी।

प्रचार सामग्री वितरण में अवरोध के विरुद्ध भाजपा पहुंची चुनाव आयोग

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग संपर्क समिति संयोजक डॉ. विजय शंकर मिश्रा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को शिकायत कर प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस के द्वारा भाजपा की प्रचार सामग्री के वितरण में अवरोध पर कार्यवाही की मांग की। निर्वाचन आयोग को की गई शिकायत में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सशक्त एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भाजपा के द्वारा विधान-सभा चुनाव 2023 हेतु जारी अपने चुनाव घोषणा-पत्र में महिला वंदन योजना प्रस्तावित की गयी है। अनायास रूप से आज ही लगभग समस्त जिलों से चुनाव में नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों तथा पुलिस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जबरन प्रचार सामग्री जप्त कर लेने, उनको प्रचार सामग्री वितरण से रोकने, बिना कारण डांट-फटकार कर एफआईआर दर्ज करने की धमकी देकर डराने-धमकाने तथा जन-संपर्क करने में रोकने की अनेकों शिकायतें प्राप्त हुई हैं ड्ड जब इन प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों से अचानक इस प्रकार रोक-टोक का कारण पूछा गया तब लगभग सभी स्थानों पर पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उन्हें ऊपर से ऐसा करने के मौखिक निर्देश हैं ड्ड शिकायत में भाजपा ने कहा कि चुनाव घोषणा के उपरांत प्रशासन का संचालन चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है।

भाजपा सरकार में किसान बेचेंगे अपना धान एकमुश्त : साव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के पाँच दिन बीत जाने के बाद भी 10 जिलों के 1361 केंद्रों में धान खरीदी की शुरुआत नहीं होने को प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उन घोषणाओं पर किसानों का गहन अविश्वास बताया है, जो इन दिनों येन-केन-प्रकारेण सत्ता हासिल करने की जद्दोजहद में कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। श्री साव ने कहा कि किसानों के साथ छल-कपट और झूठ-फरेब करके भूपेश सरकार अपना समूचा राजनीतिक वजूद दाँव पर लगा चुकी है और अब वह तमाम कोशिशों के बाद भी किसानों का भरोसा वापस नहीं पा सकेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि भाजपा किसानों को कांग्रेस से ज्यादा राशि एकमुश्त देने जा रही है कांग्रेस शासन में 4 किश्तों में अपने हक की राशि पाकर किसान खुद को ठगा हुआ पा रहा है। कांग्रेस सरकार ने किसानों को किसान सम्मान निधि से भी वंचित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ।,प्रदेश में धान खरीदी शुरू हुए पाँच दिन बीत जाने के बाद भी 10 जिलों के 1361 केंद्रों में धान खरीदी की बोहनी तक नहीं होना यह दर्शाता है कि किसान अब कांग्रेस की घोषणाओं पर कतई भरोसा नहीं कर रहे हैं। भाजपा कांग्रेस से ज्यादा धान की खरीदी करने जा रही है वह भी प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रू की मूल्य से किसानों को एकमुश्त भुगतान करने जा रही है इससे किसानों में खुशी की लहर है और वह अब भाजपा सरकार में अपना धान बेचने चाह रहे है। भाजपा किसानों के बच्चो को 2 लाख तक की स्कॉलरशिप भी देगी साथ ही 25 दिसंबर को 2 साल के बोनस का एकमुश्त भुगतान भी करेगी।

प्रमुख समाचार छत्तीसगढ़/राजधानी

बिलासपुर महापौर रामशरण यादव पार्टी से निलंबित

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने बिलासपुर महापौर रामशरण यादव को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है. इसके अलावा मनीष श्रीवास्तव, शिशिर श्रीवास्तव और सुरेश पाटले को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है.कभी यह सब मोहन मरकाम के खास हुआ करते थे लेकिन इस चुनाव में सब ने पार्टी के खिलाफ भीतर घात किया इसलिए मनीष श्रीवास्तव, शिशिर श्रीवास्तव और

सुरेश पाटले को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है. बागी प्रत्याशी व पूर्व कांग्रेस विधायक अरुण तिवारी और मेयर रामशरण यादव के बीच टिकट बंटवारे को लेकर ऑडियो वायरल हुआ था. बातचीत के वायरल ऑडियो में कांग्रेस के टिकट बंटवारे में 4 करोड़ रुपये की डील की बात हुई थी. जिसपर पीसीसी ने मामले में संज्ञान लिया था. एक दिन पहले ही पीसीसी ने मेयर को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा था. संतोषजनक जवाब न मिलने पर आज पीसीसी ने निलंबन का आदेश जारी किया है.निलंबन आदेश में लिखा गया है कि, दीपक बैज के आदेशानुसार विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते और कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण रामशरण यादव, महापौर बिलासपुर की आज 10 नवंबर से प्राथमिक सदस्यता निलंबित की जाती है।

भूपेश सरकार के योजनाओं का नतीजा है बाजार में रौनकः ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भूपेश सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का असर धनतेरस के दिन बाजार में रौनक दिख रहा है बीते 5 साल में भूपेश सरकार ने जनता के जेब में 175000 करोड रुपए डाले हैं जिसके चलते आज मोबाइल बाजार, ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्लॉथ ज्वेलरी, किराना सहित सभी शौक और जरूरतों के समान वाले दुकानों में आज भरपूर ग्राहकी

नजर आ रही है। 9 साल में मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते देश मंदी महंगाई और बेरोजगारी के अभूतपूर्व दौर से गुजर रहा है। देश के कई राज्यों में दिवाली में भी किसानों नौजवानों के चेहरे में मायूसी दिख रही है बेबसी दिख रही है। देश के संसाधन बिक रहे है मोदी सरकार के दौरान ही देश पर कुल कर्ज का भार 3 गुना बढ़ चुका है। बेरोजगारी, महंगाई, असमानता और भुखमरी बढ़ रही है। मोदी राज में देश की अर्थव्यवस्था उल्टे पाव भाग रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की न्याय योजना सबके साथ खड़ी हुई है, किसानों को उनकी उपज का सही कीमत मिल रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहे, बिजली बिल हाफ की सुविधा मिल रही है, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, आदिवासी वर्ग को उनके वनोपजों का समर्थन मूल्य मिल रहा है, तेंदूपत्ता की कीमत 4000 रु प्रति मानक बोरा मिल रहा ,धनवंतरी मेडिकल स्टोर में दवाइयों में 73 प्रतिशत तक की छूट, अंग्रेजी माध्यम की निशुल्क शिक्षा जिसके कारण मोदी निर्मित महंगाई से प्रदेश की जनता सीधी लड़ाई लड़ पा रही है।

चुनाव हारता देख बृजमोहन झूठी कहानी गढ़ रहेः शुक्ला

रायपुर। भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल द्वारा अपने ऊपर हमले के दावों को प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है, यह चुनाव हारते हुये प्रत्याशी की नई नौटंकी है। बृजमोहन अग्रवाल का सारा चुनावी मैनेजमेंट महंत रामसुंदर दास की सरलता और निश्छलता के सामने फेल हो गया है। बृजमोहन अग्रवाल का

दक्षिण से चुनाव हारना तय है, दक्षिण की जनता ने अबकी बार बृजमोहन से छुटकारा पाने का मन बना लिया है। दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशी महंत रामसुदंर दास सरल सहज और सहृदयी संत है। वे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े धर्म गुरू है। उनकी मृदुभाषी आचरण से रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मतदाता उन्हें हाथों हाथ ले रहे, क्षेत्र के महिला, पुरूष सभी महंत जी की जीत सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है। दक्षिण क्षेत्र में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनाव प्रचार कार्यक्रम भी था। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उमड़े जनसैलाब महंत श्री रामसुंदर दास को मिल रहे जनसमर्थन से बृजमोहन अग्रवाल बौखला गये है। बौखलाहट में वे सहानुभूति पाने नौटंकी कर रहे है। कांग्रेस प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास की लोकप्रियता के सामने बृजमोहन और भाजपा अपना पसंदीदा सांप्रदायिकता का गंदा खेल भी नहीं खेल पा रही है तो क्षेत्र में तनाव पैदा करने की नीयत से वे हमले की झूठी कहानी गढ़ रहे है।

भाजपा के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र पर जनता देगी जवाबः वर्मा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र ही छत्तीसगढ़िया विरोधी है। 15 साल रमन सिंह को अवसर मिला था, छत्तीसगढ़ के बहुसंख्यक आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का भला कर सके। भाजपा

नेताओं को 15 साल अवसर था कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति और समृद्धि का संरक्षण और संवर्धन करते, लेकिन भाजपाइयों ने स्थानीय छत्तीसगढ़िया जनता की उपेक्षा ही किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में सर्व समाज को आरक्षण देने का काम पूरी ईमानदारी से किया है। 76 प्रतिशत वाले नवीन आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लोगों को भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस की जनगणना के लिए क्वांटीफायबल डाटा आयोग का गठन कर प्रमाणिक आंकड़े जुटाए गए। विधि विभाग से परीक्षण के बाद विधानसभा में 2 दिसंबर 2022 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित हुआ है जिसमें सभी वर्गों की आबादी के अनुसार निर्णय लिया गया है यह विधेयक यदि कानून का रूप लेता तो हर वर्ग के लोग संतुष्ट होंते।

भाजपा देने जा रही है केंद्र के बराबर डीए और एरियर्स : पांडे

रायपुर। सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि भाजपा ने कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सौ दिन में कमेटी बनाने, केंद्र के समान डीए देने और बकाया एरियर्स देने का वादा अपने संकल्प पत्र में किया है। भूपेश बघेल ने 5 साल तक कर्मचारियों को सिर्फ धोखा देने का काम किया है। पिछले चुनाव में किए गए सारे वादे झूठे साबित हुए। सांसद संतोष पांडेय

ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सोशल मीडिया पर यह कहना सरासर धोखेबाजी है कि हम राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए देना चाहते हैं, इसके लिए अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं। यह किसको नहीं पता कि चुनाव आचार संहिता के दौरान इस तरह की अनुमति किसी भी हालत में नहीं मिल सकती। पहले चरण की 20 सीटों पर कांग्रेस की करारी हार का अंदाज कर चुके भूपेश बघेल ने अब कर्मचारियों के साथ नए सिरे से धोखेबाजी करने का जो यह प्रपंच रचा है, वह कर्मचारी अच्छी तरह समझ रहे हैं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कर्मचारियों के कल्याण की गारंटी दी है। जिसमें हमने केंद्र के सामान डीए देने की गारंटी दी है। हम कर्मचारियों को एरियर्स की राशि उनके जीपीएफ में देंगे।राज्य के कर्मचारी यह भी जानते हैं कि भूपेश बघेल ने 5 साल तक राज्य के कर्मचारियों को डीए के लिए कितना तरसाया है और हालत यह रही कि इतिहास में पहली बार मंत्रालय से लेकर न्यायालय तक के कर्मचारी डीए का हक पाने के लिए काम बंद करने पर मजबूर हुए।

अमित शाह के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने भरी हामी, कहा-

जरूर दी जाएगी ओपी चौधरी को आने वाले दिनों में बड़ी जिम्मेदारी

रायपुर। कलेक्टर पद छोड़कर भाजपा का दामन थामे पूर्व आईएएस ओपी चौधरी इन दिनों सुर्ख़ियों में हैं और हो भी कैसे न केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जो उन्हें विधायक बनने के बाद बड़ा आदमी बनाए जाने की बात कह दी है. इससे पार्टी में भी खलबली मच गई है. बात यह चल रही है कि अगर विधानसभा चुनाव बीजेपी जीतती है तो उन्हें पार्टी बड़ा चेहरा बनाकर पेश करेगी. इसपर अब पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अगर अमित शाह ने कहा तो जरूर उन्हें आने वाले दिनों में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी.

पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के भाजपा नेता और रायगढ़ के प्रत्याशी ओपी चौधरी को बड़ा आदमी बनाए जाने बयान पर कहा कि अगर अमित शाह ने कहा तो जरूर उन्हे आने वाले दिनों में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी.

पीसीसी चीफ दीपक बैज के लाशों पर सियासत वाले बयान पर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट और साफ राजनीति करती है. षड्यंत्र करने का काम कांग्रेस का है.

रायपुर के बैजनाथपारा में भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर हमले को लेकर रमन सिंह ने कहा कि राजधानी का ये हालत है कि विधानसभा के प्रत्याशी और सबसे सीनियर विधायक बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ पर आक्रमण हो सकता है. ये इस बात को साबित करता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी चौपट हो गई है. अब कांग्रेस के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं.

बता दें कि गुरुवार को रायगढ़ में रोड शो के दौरान अमित शाह ने कहा कि मैं जब भाजपा का अध्यक्ष था तब मैंने ओपी चौधरी को कहा था कि इस्तीफा मत दो, तुम चीफ सेक्रेट्री बनोगे. लेकिन इसने कहा कि नहीं, बहुत हो गई नौकरी, अब इस्तीफा देकर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करना है. इसके बाद शाह ने कहा कि ओपी चौधरी को एक बार विधायक बनाओ, उसे बड़ा आदमी बनाने की ज़िम्मेदारी मेरी है'.

योगेश ने प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष पद के लिए भरा नामांकन

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन के 26/11/23 को होने वाले अध्यक्ष पद हेतु योगेश अग्रवाल ने आज अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरा । नामांकन के आखरी दिन प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष पद हेतु योगेश अग्रवाल ने 4:15 मिनट पर मुख्य चुनाव अधिकारी दिलीप अग्रवाल एवम सहायक चुनाव अधिकारी मोहन अग्रवाल को अपना नामांकन जमा किया । योगेश अग्रवाल प्रदेश एसोसिएशन के 2000-2018 तक अध्यक्ष रहे । वर्तमान में योगेश अग्रवाल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट

ऑल इंडिया राइस मिलर एसोसिएशन अध्यक्ष, अंतराष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन छत्तीसगढ़ अध्यक्ष, व्यापार मंडल अध्यक्ष , छत्तीसगढ़ सीने एसोसिएशन छत्तीसगढ़ अध्यक्ष, कवि संगम छत्तीसगढ़ संरक्षक रायपुर जिला राइस मिल एसोसिएशन के साथ ही अनेक सामाजिक एवम व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। आज नामांकन जमा करने के अवसर पर प्रमुख रूप से विजय शर्मा शबीर भाई प्रमोद जैन शेख निरुदीननरु भाई मनोज अग्रवाल ईश्वर ललवानी विवेक कुमार अग्रवाल मोहम्मद शरीफ लाल बहादुर गुप्ता कुलदीप कुमार संजय अग्रवाल विकी शर्मा अमित अग्रवाल टीनू अग्रवाल राहुल टांटिया दीपक अग्रवाल प्रमोद अग्रवाल महेश अग्रवाल सत्यवान अग्रवाल विनोद अग्रवाल अशोक अग्रवाल के साथ ही बड़ी संख्या मैं मिलर उपस्थित थे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.